ELITE IAS

समसामयिकी

जून- 2018

8899999931/34

A-1 Chandra House, Top Floor, (Opp. ICICI Bank), Mukherjee Nagar, Delhi-09

ELITE IAS

Our Courses

For Civil Services Preparation

CLASSROOM PROGRAM

Hindi / English

Upgraded Foundation Course
General Studies

ONLINE COURSES

General Studies Video Classes
(Interactive)

ALL INDIA TEST SERIES

Hindi / English

General Studies
Prelims + Mains + Essay

CORRESPONDENCE COURSES

General Studies Pre. & Mains
(Interactive)

Index

आलेख

1.	निपाह जैसे संक्रमण से लड़ने की चुनौती	1-2

कला, संस्कृति, समाज एवं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

2.	स्वच्छ सर्वेक्षण, 2018 रिपार्ट: इंदौर दूसरे वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर	3-4
3.	लैंगिक असमानता के कारण भारत में प्रतिवर्ष, 2,39,000 लड़कियों की हत्या: लांसेट रिपोर्ट	4-5
4.	आन्ध्र प्रदेश ने नये राजकीय प्रतीकों की घोषणा की	5-6
5.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया	6-7
6.	पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार अनिवार्य नहीं	7-8
7.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा फैकल्टी के लिए ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू किया	8-9

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

8.	राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन	10-10
9.	समग्र शिक्षा अभियान	11-11
10.	प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश सीमा दोगुनी करने को मंजूरी	12-12
11.	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति	13-13
12.	राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर	14-15

अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत एवं विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

13.	अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की	16-17
14.	भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किये	17-18
15.	एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर	18-19
16.	कोलंबिया नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश	19-20
17.	भारत और पनामा ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये	20-21

18.	आयरलैड में जनमत संग्रह से 'गर्भपात' पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया	21-22
19.	भारत ने चीन में अपना दूसरा आई.टी कॉरिडोर आरंभ किया	23-24
20.	भारत और नीदरलैंड के मध्य 50 समझौतों पर हस्ताक्षर	24-25
21.	प्रधानमंत्री मोदी और व्लांदिमीर पुतिन के बीच अनौपचारिक शिर बैठक	25-26
22.	क्लैंपडाउंस एंड करेज-साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18	27-28

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

23.	भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता	29-30
24.	विदेश से धन भेजने के मामले में भारतीय दुनिया में सबसे आगे	30-31
25.	भारत ने विश्व बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया	31-32
26.	मुद्रा योजना को बढ़ावा देने हेतु 40 कम्पनियों के साथ समझौता	32-33
27.	व्यापार आशावाद सूचकांक	34-34

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य

28.	डब्ल्यूएचओ ने पहली आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची जारी की	35-36
29.	स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भारत 145वें स्थान पर: लांसेट रिपोर्ट	36-37
30.	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में रूपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप लॉन्च किया	37-38
31.	3डी प्रिंटेड कॉर्निया विकसित	38-39
32.	भारत-रूस के मध्य अत्याधुनिक एस-400 सिस्टम खरीदने हेतु समझौता	39-40
33.	भारत-नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण- XIII उत्तराखंड में आरंभ	40-41
34.	यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखा गया	41-42
35.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस-2018	42-42
36.	रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने रक्षा बलों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी।	43-44
37.	नौसेना बेड़े में लैंडिंग क्राफ्ट यूटीलिटी एमके-IV के चौथे जहाज को शामिल किया गया	44-45

38.	रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयत्र लॉन्च किया	45-46
39.	निपाह वायरस	46-47
40.	नीति आयोग और एबीबी ने आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया	47-48
41.	ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण	48-49
42.	बौद्धिक संपदा के मस्कट 'आईपी नानी' का शुभारंभ	50-51
43.	WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्ति हेतु रिप्लेस गाइड जारी की	51-52
44.	भारतीय सेना ने 15,000 करोड़ रुपये की हथियार उत्पादन परियोजना को मंजूरी दी	52-53
45.	भारतीय सेना का युद्धाभ्यास 'विजय प्रहार' सफलतापूर्वक संपन्न	53-53
46.	सेना पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ भारत	54-55
	पारिस्थितिकी और पर्यावरण	
47.	अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	56-56
48.	उत्तर पूर्व में 'गज यात्रा' आरंभ की गई	57-57
49.	वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन हैम्बर्ग में आयोजित किया जाएगा	58-59
50.	भारत में सिंधु डॉल्फिन की पहली संगठित जनगणना आरंभ की गई	59-60
	आंतरिक सुरक्षा	
51	स्थानीय आदिवासियों से निर्मित बस्तरिया बटालियन सी.आर.पी.एफ में शामिल	61-62
	अन्य `बरें	
52.	कैलाश सत्यार्थी और किरण कुमार 'संतोकबा ह्यूमैनेटेरियन अवार्ड' से सम्मानित	63-63
53.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	63-63
54.	पंकज सरन भारत के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त	63-64
55.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)	64-66
56.	पोलैंड की ओल्गा टोकर्कजुक ने मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त किया।	66-67
57.	उच्चतम पछरने को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।	67-67

58.	भारतीय मूल के वैज्ञानिक ई.सी. जॉर्ज सुदर्शन का निधन	68-68
59.	विश्व के सबसे ताकतवार लोगों की सूची	68-69
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योयोगिकी दिवस 2018 मनाया गया	69-69
61.	राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए	69-72

आलेख

निपाह जैसे संक्रमण से लड़ने की चुनौती

- हमारे देश में बीमारियों का भी चक्र चलता है। एक का खतरा कम नहीं होता कि दूसरे की आशंका घेरने लगती है। इनमें कई तो मौसमी बदलाव और तापमान के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं।

  लगभग हर बरस ऐसे देश का सामना करने के बावजूद हमारी चिकित्सकीय प्रणाली उसकी अभ्यस्त नहीं हो सकी हैं। हां हमारा शरीर जरूर धीरे-धीरे उनका आदी हो जाता है। जब जाने-पहचाने रोगों का ये आलम है तो फिर निपाह वायरस जैसा नया और अनजाना रोग किस कदर तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा बूबी लगाया जा सकता है। इसकी जद में आने से मुल्क के दक्षिणी राज्य केरल में मौतें होने से हड़कंप मच गया है।

- काफी सतर्कता बरने पर स्थिति थोड़ी काबू में जरूर आई, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। संक्रमण फैलने का भय बदस्तूर कायम हैं अब तक इससे मरने वालों की संख्या एक दर्जन से अधिक हो गई है। इसमें निपाह वायरस से पीड़ित रोगियों का इलाज करने वाली एक नर्स लिनी भी शामिल हैं इन सबके बावजूद अब तक गनीमत ये है कि इसका संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है जितनी तेजी से स्वाइन फ्लू या फिर डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। निपाह वायरस के खौफ से जो मरीज अस्पतालों में दाखिल भी हो रहे हैं, उनमें अधिकतर में इसका संक्रमण नहीं पाया गया है। तसल्लीबख्श ये भी है कि इसके कदम अभी केरल की सीमाओं को लांघकर दूसरे राज्यों में भी नहीं पहुंच सके हैं। तो क्या इसे महज इसे अपनी खुशनसीबी समझकर हमें भगवान भरोसे बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जरा सी सावधानी हटने से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कारण निपाह वायरस के रोग काफी रहस्यमय होना है।

क्या है निपाह वायरस?

- निपाह वायरस एक नई और उभरती हुई बीमारी है। इसलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है। अलबत्ता अब तक इसके जो तथ्य और प्रमाण सामने आए हैं उसके अनुसार इसका नाम निपाह मलेशिया के एक गांव 'सुनगई निपाह' पर पड़ा जहां 1998 में पहली बार इस रोग की पहचान हुई थी। वहां सूअरों में फैले इसके संक्रमण की वजह से एक साल के भीतर 100 लोग अकाल ही काल का ग्रास बन गए थे और तकरीबन 300 लोग संक्रमित हुए थे। उस समय मलेशिया में इस बीमारी को रोकने के लिए लाखों सूअरों को मार दिया गया था। इस बीमारी पर किए गए अनुसंधान में ये सामने आया कि इसका संक्रमण इंसानों के अलावा फल खाने वाले चमगादड़, सूअर, गाय और अन्य जानवरों से भी फैलता है। संक्रमित फल खाने से भी ये फैलता है।

- अब तक फल खाने वाले चमगादड़, सूअर और पालतू जानवरों को इसके वायरस का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। केरल में भी इस बीमारी के फैलाने में फल खाने वाले चमगादड़ों को ही सबसे बड़ा वाहक माना गया। ऐसे अकारण भी नहीं है, कयोंकि केरल के जिस पेरांबरा गांव में निपाह वायरस की वजह से शुरुआती मौत की सूचना मिली थी, वहां एक घर के कुंए में कई चमगादड़ मरे पाए गए थे। कोडिकोड जिला के उस घर के मुखिया मूसा समेत अब तक चार लोगों

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

की इस निपाह वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। हालांकि भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों की जो बिल्कुल ताजा रिपोर्ट आई है, उनमें इस चमगादड़ों समेत दीगर जानवरों में निपाह विषाणु नहीं मिले हैं। इससे जाहिर है कि या तो निपाह वायरस के संक्रमण की कोई और वजह है या फिर ये जानवरों नहीं, बल्कि इंसानों के जरिये ही फैला है। मूल कारण तो और गहन छानबीन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन लैब से मिली इन ताजा रिपोर्टों ने पहले से ही काफी रहस्यमय माने जाने वाले निपाह वायरस के राज को और उलझा दिया है।

- निपाह विषाणु से संक्रमित व्यक्ति के दिमाग में इन्सेफाइटिस जैसी तेज सूजन आ जाती है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र के अनुसार संक्रमण के तीसरे दिन से नजर आने शुरू होते हैं और जल्द ही व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आरंभ में बुखार, उल्टी और तेज सिरदर्द की शिकायतें होती हैं। कुछ-कुछ मरीजों में सांस लेने की दिक्कत रहती हैं इन शुरुआती लक्षणों के बाद मरीज का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है या उसकी चेतना में गिरावट आने लगती है। फिर कोमा में चला जाता है और उसकी मौत तक हो जाती है। निपाह वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके कारण होने वाली मृत्यु दर 70 फीसद है।
- चिकित्सा विज्ञान के काफी तरक्की कर जाने के बावजूद निपाह वायरस का अब तक कोई कारगर इजाल नहीं ईजाद हो पाया है। निपाह वायरस से संक्रमित इंसानों और जानवरों के इलाज के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए बचाव और उचित देखभाल को ही इससे बचने का अब तक सबसे बेहतर तरीका माना गया है। निपाह संक्रमित रोगी को दीगर लोगों से अलग-थलग रखकर इसके फैलाव को रोका जा सकता है। समय रहते ऐसे ऐहातियाती कदम उठाने की वजह से ही केरल में ये संक्रमण भयावह रूप लेने से बच गया है।
- नई और रहस्यमयी बीमारी होने के कारण निपाह को समझने में ही देर हो जाती है। ऊपर से कोई इलाज संभव नहीं होने की वजह से इसके खतरे और अधिक हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन का मुंह ताकने के बजाय बेहतर ये है कि स्वयं इससे बचा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि संक्रमण वाली जगह और वहां के लोगों व जानवरों के संपर्क में आने से बचा जाए। साथ ही किसी जानवर, परिंदे या कीड़े के आंशिक रूप से खाए हुए फलों का सेवन बिल्कुल मत करें और अगर इस बीमारी के लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें।
- देखा जाए तो केरल के अलावा केंद्र सरकार के जरिये इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अब तक उठाए गए कदम काफी कारगर साबित हुए हैं। निपाह वायरस को केरल तक ही सीमित करके उस पर काबू पा लेना बड़ी उपलब्धि है। दीगर राज्यों की सरकारों ने भी इसके लिए अलर्ट जारी करके सराहनीय प्रयास किया है। फिलहाल हम इस बीमारी को परास्त करते जुरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी इसके खतरों से बचने के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कला, संस्कृति, समाज, तथा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे

स्वच्छ सर्वेक्षण, 2018 रिपार्ट: इंदौर दूसरे वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर

चर्चा में क्यों?

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत किये गए सर्वेक्षण के तहत 16 मई, 2018 को परिणाम घोषित किए गए। इस वर्ष के सर्वेक्षण परिणामों में इंदौर लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया जबकि राजधानी की श्रेणी में मुंबई को स्वच्छता के मामले में देश में पहला स्थान मिला है।
- देश भर के चार हजार से अधिक शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया गया था इस सव्रेक्षण में पिछली बार की तरह इस बार भी इंदौर टॉप पर है, जबकि मध्य प्रदेश का ही दूसरा शहर भोपाल दूसरे नंबर पर है एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराये गये स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 3 स्रोतों से आंकड़ें जुटाये गये।

क. सेवा स्तर में हुई प्रगति

क. प्रत्यक्ष निरीक्षण

ग. नागरिकों का फीडबैक

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 संबंधी आंकड़े

सबसे स्वच्छ शहर	इंदौर
सबसे स्वच्छ बड़ा शहर (1 मिलियन आबादी)	विजयवाड़ा
सबसे स्वच्छ मध्यम शहर (3-10 लाख आबाद)	मैसूर
सबसे स्वच्छ छोटा शहर (1-3 लो आबादी)	एनडीएमसी
सबसे स्वच्छ राजधानी	ग्रेटर मुंबई
सबसे स्वच्छ छावनी	दिल्ली कैंट

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के प्रमुख तथ्य

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, शहरी भारत में स्वच्छता का आकलन करने वाला अखिल भारतीय अभ्यास था, जिसमें 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 तक 4,203 शहरों का सर्वेक्षण किया गया।
- इस रैंकिंग में मध्यप्रदेश का शहर इंदौर नंबर एक स्थान पर है भोपाल दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तेजी बदलता बड़ा शहर माना गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- स्वच्छता के मामले में झारखंड को सबसे बेस्ट परफॉर्मेस शहर बताया गया है इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है।
- पिछले वर्ष 2000 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन इस बार 4000 से अधिक शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश भर के शहरों में स्वच्छता स्तर का आकलन करना है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों के नाम उस दिन घोषित किए जाएंगे जिस दिन पुरस्कार दिए जाएंगे।
- केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक बजट में 33,875 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए ही प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू

लैंगिक असमानता के कारण भारत में प्रतिवर्ष, 2,39,000 लड़कियों की हत्या: लांसेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था द लासेंट द्वारा 15 मई, 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लैंगिक भेदभाव के कारण 2,39,000 नवजात लड़कियों को मारा जाता है।
- लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियां भारत में बेटों के लिए समाज की प्राथमिकता के परिणामस्वरूप उपेक्षा के कारण मारी जा रही है।
- शोधकर्ताओं द्वारा यह रिपोर्ट द लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित की गई।

लांसेट रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- पेरिस डेसकार्ट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता क्रिस्टोफ गुइलमोतो ने इस अध्ययन की अगुवाई की
- गुइलमोतो और उनकी टीम ने समाज में लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के लिए 46 देशों से आबादी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया।
- शोधकर्ताओं ने इस बात को प्रमुखता से अध्ययन किया कि लैंगिक असमानता के कारण किस देश में कितनी नवजात अथवा व्यस्क लड़कियों को मारा जाता है।
- यह अंतर वर्ष 2000 और 2005 के बीच पैदा हुई हर 1,000 लड़कियों में किया गया जिसमें भारत में प्रत्येक 19 मौतें लिंग पूर्वाग्रह के प्रभावों के कारण हुई थीं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत में महिलाओं के कुल मृत्यु दर का लगभग 22 प्रतिशत लिंग पूर्वाग्रह के कारण भ्रूण हत्या है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तरी भारत में समस्या सबसे अधिक स्पष्ट थी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को अवयस्क लड़कियों की मृत्यु के दो तिहाई हिस्से के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

लैंगिक भेदभाव	***लैंगिक समानता***
❑ महिलाओं या लड़कियों के साथ हो रहे लैंगिक भेदभाव का अर्थ न केवल उन्हें जन्म से पूर्व मृत्यु के घाट उतार देना है बल्कि जन्म के बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जाना लैंगिक भेदभाव में शामिल है।	लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं को शिक्षा, रोजगार एव राजनीति में भागीदारी के समान अवसर दिया जाना है। इसमें नवजात कन्याओं को उचित देखभाल, टीकाकरण एवं पोषण दिया जाना भी शामिल है।

कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के भारतीय महिला नेटवर्क (IWN) और ईवाई (EY) द्वारा कराये गयेदेशव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार 16% संगठनों के निदेशक मंडल में कोई महिला नहीं है। वहीं 47% में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या 5% से अधिक नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल 42% महिलाओं ने कहा कि उनके साथ प्रबंधकीय पक्षपात होता है जबकि 33% महिलाओं का मानना है कि कार्यस्थल पर महिला ओर पुरुषों के काम और प्रदर्शन के लिए अलग मानक हैं।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

आन्ध्र प्रदेश ने नये राजकीय प्रतीकों की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- आंध्र प्रदेश के विभाजन के चार वर्ष बाद 30 मई, 2018 को आंध्र प्रदेश के पर्यावरण, वन, विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा राज्य के नये राजकीय चिह्नों की घोषणा की गई।

मुख्य तथ्य

- इसमें आंध्र प्रदेश के राजकीय पक्षी एवं राजकीय पशु के नाम घोषित किये गये हैं। सरकारी घोषणा के अनुसार राजकीय चिह्नों में विभाजन के उपरांत यह बदलाव किया जाना आवश्यक था क्योंकि इससे राज्य की पृथक पहचान सुनिश्चित हो सकती है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को दो भागों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में बांटा गया था।
- विभाजन के उपरांत तलंगाना में चले गये आंध्र प्रदशे के कुछ भाग से आंध्र प्रदेश की पारिस्थितिकी भी दो भागों में विभाजित हुई जिसके चलते नये राजकीय चिह्न जारी करना आवश्यक था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आंध्र प्रदेश के राजकीय प्रतीक

- **राजकीय पक्षी:** रामा चिलुका (Psittacula Krameri)।
- **राजकीय वृक्ष:** नीम (Azadirachta Indiaca) स्थानीय भाषा में वेपा चेट्टू।
- **राजकीय पशु:** कृष्णा जिंका (Antilope Cervicapra) अथवा ब्लैक बक।
- **राजकीय फूल:** चमेली (asminnum Officinale)।

तेलंगाना के राजकीय प्रतीक

- **राजकीय पक्षी:** पलापित्ता अथवा इंडियन रोलर (Coracias Benghalensis) यह ओडिशा और कर्नाटक का भी राजकीय पक्षी है।
- **राजकीय वृक्ष:** जम्मी चेट्टू (Prosopis Cineraria)

  राजकीय पशु: जिंका अथवा स्पॉटेड हिरन।
- **राजकीय फूल:** तंगीडी पुव्वु (Senna Auriculata) इसे राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार बठुकम्मा में प्रयोग किया जाता है।
- वर्ष 1985 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपना राजकीय पक्षी, पशु, वृक्ष और पुष्प निह्नित करते हुए अधिघोषित करने के लिए कहा था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई, 2018 को कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले में 330 मेगावॉट किशनगंगा जलविदयुत परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना की प्रगति की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी की गई थी। उन्होंने डल झील पर स्थित शेर-ए-कश्मीर कन्वेंशनल सेंटर से इसका उद्घाटन किया।

किशनगंगा पनबिजली परियोजना

- इस परियोजना का निर्माण जनवरी, 2009 में तीन मोर्चों पर शुरू हुआ हेड रेस टनल (एचआरटी), पावर हाउस और वेंटिलेशन टनल।
- इस परियोजना से प्रतिवर्ष 171.3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।
- परियोजना से उत्पादित 12 प्रतिशत बिजली जम्मू-कश्मीर को और शेष अन्य राज्यों को प्रदान की जाएगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- यह परियोजना सीस्मिक जोन-4 में स्थित है और ब्रिटिश कम्पनी हाल्क्रो द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि भूकम्प को झेलने में सक्षम है।
- परियोजना को मूर्त रूप देने का उत्तरदायित्व एन.एच.पी.सी. को दिया गया जिसने आई.आई.टी. रुड़की से परियोजना को सही रूप देने के लिए सलाह ली।

पृष्ठभूमि

- 2005-06 में जब भारत ने किशनगंगा जलविद्युत परियोजना की परिकल्पना की थी तब से ही पाकिस्तान ने सिन्धु जल संधि 1960 के उललंघन का आरोप लगाकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया था।
- पाकिस्तान ने वर्ष 2010 दिसंबर, 2013 को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए भारत को इस परियोजना (किशनगंगा बांध) के निर्माण की मंजूरी दी थी।
- सितम्बर, 2016 में फिर से पाकिस्तान ने परियोजना का काम रोकने के लिए विश्व बैंक से अपील की तथा बांध के नजदीक आंतकी हमला भी किया गया।

सिन्धु जल सन्धि एवं विवाद

- विश्व बैंक की मध्यस्थता से वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिन्धु नदी के जल अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। सन्धि के अनुसार हिमालय क्षेत्र की 6 प्रमुख नदियों में से 3 पश्चिम नदियों-सिन्धु झेलम और चिनाव के पानी के प्रयोग का हक पाकिस्तान और 3 पूर्वी नदियों-सतलुतज, रवि व व्यास के प्रयोग का हक भारत को दिया गया है।
- किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी पर सिथत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसकी अनुमति इस संधि में दी गई है। इस नदी के कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से मात्र 50 किमी भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है शेष 195 किमी पाक अधिकृत कश्मीर में इसी के चलते पाकिस्तान ने इस परियोजना में अड़ंगा डालने की हमेशा कोशिश की लेकिन संधि की शर्तों के चलते उसे सफलता नहीं मिली।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार अनिवार्य नहीं

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।

मुख्य तथ्य

- स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की हाल में हुई 30वीं बैठक में कार्मिक राज्य मंत्री ने जानकारी साझा की थी।
- इसके जरिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिये बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

महत्व:

- आधार कार्ड को लेकर घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी।

पृष्ठभूमि:

- आधार 12 अंकों की संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पत्ते का प्रमाण होगा।
- इस प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी, 2009 को एक अधिसूचना के द्वारा योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में 115 अधिकारियों और स्टाफ की कोर टीम के साथ की गई।
- केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61017 लो पेंशनभोगी हैं।
- केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक, कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लो रुपये तथा निर्धारित चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 01 जुलाई, 2017 से उपस्थिति भत्ता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,750 रुपये कर दिया गया है। फाइनेंस बिल 2018 में अर्जित इंटरेस्ट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं।

स्रोत: द हिंदू

❒ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा फैकल्टी के लिए ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम शुरू किया

चर्चा में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमओओसी प्लेटफॉर्म सवयं का उपयोग करते हुए 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा फैकल्टी के ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले चरण में 75 अध्ययन-विषय विशेष राष्ट्रीय संसाधन केंद्र चिह्नित किये गये है।
- विभिन्न संस्थान जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और प्रशिक्षण पर बने पंडित मदनामोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पी.एम.एम.एम.एन.एम.टी.टी.) आई.आई.एस.सी. आई.यू.सी.ए.ए., आई.आई.टी. आई.आई.एस.ई.आर. एन.आई.टी. राज्य के विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केंद्र (एच.आर.डी.सी.), राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एन.आई.टी.टी.टी.आर.), आई.आई.आई.टी. और मुक्त विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एन. आर.सी.) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उद्देश्य:

- इन केंद्रों से अध्ययन-विषय विशेष में नवीनतम विकास, उभरती प्रवृत्तियों शैक्षणिक सुधार और संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तौर-तरीकों पर फोकस के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने को कहा गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

कार्यक्रम से संबंधित मुख्य तथ्य:

- इन संसाधन केंद्रों में एन.आर.सी. समाज विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग, कला, भाषा शिक्षण, वाणिज्य, प्रबंधन, शिक्षा नियोजन और प्रशासन, लोक नीति, नेतृत्व और शासन संचालन, पुस्तकालय और सूचना सूचना विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी, निर्धारण और मूल्यकांकन, अध्यापन कला और शोध विधि, नैनो साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे विभिन्न अध्ययन–विषय हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय और वरिष्ठता को परे रखते हुए सेवारत सभी शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन रिफ्रेशर मॉड्यूल विकसित करेंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ष के 15 जून तक निर्धारित विषयों की नवीनतम प्रवृत्तियां शामिल की जाएंगी।

महत्व:

- फैकल्टी को इस कार्यक्रम से लाभ होगा क्योंकि कार्यक्रम अत्यधिक लचीला है और अपने स्थान और समय के अनुसार पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन केंद्र आई.सी.टी तथा स्वयं के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर फैकल्टी के पेशेवर विकास का कार्य करेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रगति और समीक्षा के उद्देश्य से आदेश/नियम जारी करेगा।

स्वयं

- स्वयं एक ऑनलाईन लर्निंग पोर्टल है। जो विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क है। इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी नि:शुल्क है।
- स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धातों–पहुँच, निष्पक्षता तथा गुणवता को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इस पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स उपलब्ध है।
- प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से सभी शिक्षकों को स्वयं के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्रियां अपलोड करके उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसकी सफलता पर इसे जनवरी में दोहराया जाएगा।
- एन.आर.सी. 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रमाणित फैकल्टी की सूची प्रकाशित करेंगे।

स्रोत: पी.आई.वी.

ELITE IAS

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राजव्यवस्था एवं शासन, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक विकास

राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

- राज्यसभा के सभापित एम वेंकैया नायडू ने 07 मई, 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत: निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है।
- उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया है। यह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी।

समिति का स्वरूप

- समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे।
- यह समिति दो भागों में रिपोर्ट पेश करेगी और पहली रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी।
- समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो रानीतिक दलों एवं सांसदों से विचार विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों?

- बजट सत्र के दूसरे में चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पाया था। इसी के मद्देनजर नियमों में बदलाव करने हंगामा करने वालों के खिलाफ स्वत: निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है। लोकसभा की तरह, सदन में सभापित के आसन के पास आकर बार-बार हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन का प्रावधान फिलहाल राज्यसभा में नहीं है।

राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां

- लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है।
- संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए।
- लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से 14 अधिक दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। अनुच्छेद-249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समग्र शिक्षा अभियान

चर्चा में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 मई, 2018 को सरकार की महत्वकांक्षी समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधारने तथा तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाकर विद्यायार्थी और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जायेगा।
- इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है तथा साथ ही बच्चों को समग्र रूप से विकास की और अग्रसर करना है।

समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य तथ्य

- पाचवीं तक के स्कूल में खेल सामग्री के लिए हर साल 5,000 रुपये, दसवीं तक के स्कूल में 10,000 तथा 12वीं तक के स्कूलों में 15,000 रुपये दिए जाएंगे।
- सभी स्कूली में एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना अनिवार्य होगा।
- स्कूलों में लाइब्रेरी होना बेहद जरूरी है, इसके लिए केंद्र सरकार स्कूलों को किताबों के लिए हर वर्ष 5,000 से लेकर 20,000 तक की सहायता राशि मुहैया कराएगा।
- दूर-दराज और गांव में रहने वाली लड़कियों को शिक्षा देने के लिए आरंभ की गई कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना पहले छठी से नौवीं तक ही सीमित थी। इसे अब छठी से बारहवीं तक बढ़ाया गया है।
- विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 200 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा।
- कौशल भारत में विद्ययार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 9वीं के विद्ययार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।

योजना का महत्व

- समग्र विकास के लिए समग्र शिक्षा आवश्यक है जिसके चलते यह योजना महत्वपूर्ण है।
- इस योजना में तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षकों द्वारा कराई जा रही जानकारी में इजाफा हो सकेगा।
- विद्ययार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि कौशल भारत में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोतः पी.आई.बी.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश सीमा दोगुनी करने को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 02 मई, 2018 को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पी.एम.वी.वी.वाई.) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा।
- निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरंभ की गई थी।

वय वंदन योजना की नई घोषणाएं

- मौजूदा निवेश सीमा साढ़े सात लाख रुपये को बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा।
- इस योजना मे निवेश की समयसीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।
- इस योजना से वरिष्ठ नागरिक प्रति माह 10,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- मार्च, 2018 तक कुल 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।
- योजना के तहत अब तक लाभार्थी को दस साल की अवधि के लिए न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह की गारंटी दी जाती है।
- इससे पहले की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 के तहत 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभन्वित हुए थे।

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना योजना को 4 मई, 2017 को लॉन्च किया था।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वी.पी.बी.वाई.) की ही तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पी.एम.वी.वी.वाई.) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के अधिक है।
- इस योजना के अंतर्गत 8 प्रतिशत का सम एश्योर्ड भी सुनिश्चित किया गया है।
- इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) कर रही है। इसमें 10 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है।
- इसमें मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक पेंशन का चयन किया जा सकता है।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मई, 2018 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई.बी.सी.) अध्यादेश में संशोधन की घोषणा की इस अध्यादेश के विधेयक में परिवर्तित होने पर आम लोगों को अधिकार एवं बड़ी राहत मिल सकेगी।
- इस कानून के तहत अभी तक केवल वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंक और अन्य उधारदाताओं को ही ये अधिकार था कि वह अपना बकाया वापस ले सकें लेकिन आम लोगों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था।

अध्यादेश में संशोधन के मुख्य तथ्य

- आई.बी.सी कानून में ताजा संशोधन का प्रस्ताव इसमें नई धारा 29 को जोड़े जाने के एक माह बाद आया है। पिछले वर्ष नवंबर में आई.सी.सी. संहिता में संभावित बोलीदाताओं की आयोग्यता को लेकर नये मानदंड जोड़े गये थे।
- कानून में ताजा संशोधन सरकार द्वारा इस संबंध में सिफारिशें देने के लिए गठित 14 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।
- दिवाला कानून पर गठित समिति ने प्दिले महीने ही कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को दी गई अपनी सिफारिश में कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर की परियोजनाओं में मकान खरीदने वाले ग्राहकों को भी बैंकों की तरह वित्तीय कर्जदाता की श्रेणी में माना जाना चाहिए।
- समिति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.ए.मई.) को भी आई.बी.सी. कानून के तहत राहत पहुंचाने का सुझाव दिया है।

महत्व

- यह अध्यादेश इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में लाखों लोगों की शिकायत है कि उनके पैसे बिल्डर के पास फंसे हुए हैं। मकान न मिलने की स्थिति में भी उनकी जमा राशि तक वापिस नहीं की जाती।
- समिति ने सुझाव दिए थे कि घर खरीदने वाले लोग भी बैंक की तरह बिल्डर को लोन देने वालों की श्रेणी में शामिल किए जाए और घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया जाए।
- यदि कोई रिएल एस्टेट कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में घर खरीदारों की बराबर भागीदारी हो।
- ग्राहक बिल्डर को पहले पैसा देते हैं और उन्हें सालों बाद घर का पजेशन मिलता है। इस प्रकार पूरी परियोजना के तैयार होने में ग्राहक का पैसा भी शामिल होता है।

पृष्ठभूमि

- इससे पहले लोकसभा में 29 दिसंबर, 2017 को दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबी.सी.) में संशोधन का विधेयक परित हुआ था।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बकायेदार्ुद की संपत्ति की बोली नहीं लगा सकते।
- आई.बी.सी. कार्यान्वयन कॉरपोरेट मामलों द्वारा ही किया जाता है जिसे 2016 दिसंबर में लागू किया गया था, जो समयबद्ध तरीके से दिवालिया समाधान प्रक्रिया प्रदान करती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 08 मई, 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोषण अभियान भी कहा जाता है। पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है।
- प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 को झुंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था।
- यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा।
- आई.सी.डी.एस. योजना के तहत स्तनापान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) का उद्देश्य

- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी लाना है।
- बौनापन को कम करने का लक्ष्य भी 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 तक 38.4% (एन.एफ.एच.एस-4) से कम कर के 25% तक लाने का प्रयास करेगा।
- इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- यह सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा, जबकि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले एवं वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रः

- इस परियोजना में पोषण आधारित सभी योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा तथा प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, समुदायों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यश्म से बौनापन, अल्पपोषण, रक्त की कमी और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में कमी लाने का प्रयास करेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- महिलाओं को 1000 कैलोरी तथा बच्चों को 600 कैलोरी उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।
- इस लक्ष्य को पूरा करेन हेतु भोजन की पोषकता, स्तनपान के माध्यम से स्थायी समाधान, आहार विविधीकरण, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, निगरानी को उच्चस्तरीय बनाना आदि उपायों पर जोर दिया गाया है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी।

स्रोतः पीआई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध, भारत और विश्व एवं वैश्विक परिदृश्य

अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 08 मई, 2018 को ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होन की घोषणा की।

- राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बीते 15 महीनों में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह फैसला सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में ट्रंप पर दबाव बना चुके थे कि अमेरिका को इस समझौते से जुड़े रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प कई मौकों पर कह चुके थे कि यदि इस समझौते को संशोधित नहीं किया गया तो अमेरिका इस समझौते से अलग हो जाएगा।

अन्य देश:

- ईरान के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देश चाहते हैं कि ईरान के साथ तीन साल पहले हुआ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता बना रहे।

- परामाणु समझौता होने के बाद जर्मनी की कंपनियों ने भी ईरान में बड़ा निवेश किया है। हाल ही में जारी हुई जर्मनी के फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईन को जर्मनी का सालाना निर्यात वर्ष 2017 में बढ़कर 3.5 अरब डॉलर (20 हाजार करोड़ रुपये से ज्यादा) हो गया है।

अमेरिका समझौते से क्यों अलग हुआ?

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ईरान परमाणु समझौते का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईरान उसे मिल रही परमाणु सामग्री का इस्तेमाल हथियार बनाने में कर रहा है।

- परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। वे सीरिया, यमन ओर इराक में शिया लड़ाकों जेसे संगठनों को हथियार सप्लाई कर रहा है।

विश्व पर असर:

- परमाणु समझौते से अलग होने से ईरान पर दोबारा आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं जिससे वैश्विक तेल कंपनियों पर ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव बढ़ेगा।

- भारत जैसे अमेरिका के करीबी देशों ने ईरान के साथ तेल पर समझौता किया है, जो डोनाल्ड टंप के फैसले से विवाद में आएंगे। 2

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- अमेरिका के प्रति नफरत की भावना बढ़ेगी और ईरान परमाणु गतिविधियां बढ़ा देगा।
- इससे ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ेगा।

ईरान परमाणु समझौता

- ईरान परमाणु समझौता तेहरान और छह वैश्विक शक्तियों के बीच वर्ष 2015 में हुआ था, छह वैश्विक शक्तियों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस जर्मनी, रूस और ईरान शामिल हैं, इस समझौते के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था, जिसके बदले में अमरीका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी।
- समझौते के मुताबिक ईनरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था और अपने परमाणु संयंत्रों के निगरानी के लिए खोलना था, बदले में उसपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक रियायत दी गई थी।
- ये समझौता राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था। इस समझौते का दुनियाभर के कई देशों ने स्वागत किया और इसे संबंधों के सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना।

स्रोतः द हिंदू

भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों ने 30 मई, 2018 को व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में सागर (SAGAR) मंत्र दिया।

सागर (SAGAR) मंच

- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और SAGAR विजन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको जिदोदो की मैरीटाइम फलक्रम पॉलिसी से मेल खाता है। प्रधानमंत्री ने SAGAR का अर्थ बताया-सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन।
- मर्डेका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति विदोदो के सामने दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक हुई।
- जिसमें कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए भारत और इंडोनेशिया के बीच 15 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे।
- इनमें छह समझौतें विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य हुए हैं। इंडोनेशिया के बाली और भात के उत्तराखंड राज्यों को सहोदर राज्य बनाने की भी घोषणा की गयी।
- इस अवसर पर संयुक्त वक्तव्य ओर भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग पर एक अलग साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य

- दोनों पक्ष क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के शुरुआती निष्कर्ष के लिए गहन रूप से काम करने पर सहमत हुए और दोहराया कि सभी सदस्यों के लिए लाभ के साथ व्यापक, निष्पक्ष और संतुलित कार्य होना आवश्यक है।
- दोनों पक्ष संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, फिल्मों और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
- भारत और इंडोनेशिया परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयो के लिए तथा अक्षय उर्जा के उपयोग के लिए सहमत हुए
- दोनों देशों ने द्वविपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।
- भारत और इंडोनेशिया, दोनों पक्षों ने 2025 तक द्ववपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- भारत और इंडोनेशिया द्वारा वर्ष 2019 में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाए जाने की घोषणा की गई।
- शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। ये दोनों देशों के लिए खासकर युवाओं के लिए लाभकारी होगा।

स्रोतः द हिंदू

एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत चौथे स्थान र है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैाक लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में एशिया-प्रशांत के 25 देशों का आकलन किया गया, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है।,

मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया-प्रशांत में जापान और भारत दोनों बड़ी शक्तियां हैं, रिपोर्ट के अनुसार जापान जहां वर्तमान में स्मार्ट शक्ति है वहीं भारत भविष्य की विशाल शक्ति हैं।
- रिपोर्ट में रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, न्यूजीलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपींस और उत्तर कोरिया को मध्यम शक्ति (Middle Power) का दर्जा दिया गया है।
- बांग्लादेश, ब्रुनेई, म्याँमार, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस और नेपाल को मामूली ताकत (Minor Power) का दर्जा दिया गया है।

विभिन्न मानक में भारत का स्थानः

- भारत आर्थिक संसाधन, सैन्य क्षमता, राजनयिक प्रभाव के मानक पर चौथे स्थान पर हैं, जबकि लचीलेपन में पांचवे स्थान पर और सांस्कृतिक एवं भविष्य की प्रवृत्तियों के आधार पर तीसरे स्थान पर रखा गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत को आर्थिक संबंध के मानक पर सातवें स्थान पर और रक्षा नेटवर्क के मामले में दसवें स्थान पर रखा गया है, हालांकि कुल मिलाकर इस सूचकांक में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है।
- भारत भविष्य की बड़ी ताकत बनने की ओर है लेकिन रक्षा नेटवर्क और आर्थिक संबंधों की दिशा में सुधार की जरूरत है।

रैंकिंग किस आधार पर तय की गई

- ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को विभिन्न पैमाने पर आंकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विभिन्न मानकों का आधार बनाया जाता है।
- इस मानक के तहत किसी भी देश की एक बड़ी शक्ति के रूप में रैंकिंग करने के लिए उस देश की आर्थिक संसाधनों, सैन्य ताकत, लचीलेपन, भविष्य की प्रवृत्तियां, राजनयिक प्रभाव, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे आठ मानकों पर परख की जाती है।
- इस सूचकांक को तैयार करने के लिए पश्चिम में पाकिस्तान तो उत्तर मे रुस और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तक को अपने अध्ययन में शामिल करता है, रिपोर्ट में सभी पैमानों पर परखने के बाद भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है।

चीन एक उभरती हुई शक्ति:

- इस रिपोर्ट में चीन को एक उभरती हुई महाशक्ति बताया गया है, चीन तेजी के साथ अमरीका के बराबर पहुँच रही है और अमरीका एक पूर्व प्रतिष्ठित शक्ति है।
- रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन एशिया में है। अमरीका प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है रिपोर्ट के अनुसर वर्ष 2025 तक दुनिया की दो-तिहाई आबादी एशिया में होगी जबकि मात्र 10 प्रतिशत आबादी ही पश्चिम में रह रही होगी।

स्रोत: लाइव मिन्ट

कोलंबिया नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश

चर्चा में क्यों?

- कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने 25 मई, 2018 को घोषणा किया कि कोलंबिया जल्द ही औपचारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल हो जाएगा। इस पहल के साथ, कोलंबिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन जाएगा।
- संगठन में कोलंबिया एक वैश्विक 'भागीदार' के रूप में शामिल होगा, जिसका अर्थ है कि इसे सैन्य कार्रवाई में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मुख्य तथ्य:

- कोलंबिया ने अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जापान, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की भांति ही नाटो के 'वैश्विक भागीदार' में रूप में जगह बनाई है।
- कोलंबिया के साथ साझेदारी में साइबर और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और संगठित अपराध के लिंक जैसे वैश्विक सुरक्षा क्षेत्रों पर सहयोग शामिल होगा।
- हालांकि घोषणा उसी दिन की गई थी जब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) ने कहा कि कोलंबिया को आधिकारिक तौर पर समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

- उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन (नाटो) एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स , बेल्जियम में है।
- नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनियसा के रक्षा व्यय का 70% से अधिक है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं।
- इस समूह में उत्तर अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देशों के साथ कुल 29 सदस्य देश हैं।
- बर्लिन प्लस समझौता नाटो और यूरोपीय संघ के बीच का एक व्यापक पैकेज हे, जिसमें यूरोपीय संघ को किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कर्रवाई के लिए नाटो परिसंपत्तियों का उपयोग करने की छूट कदी गई है, बशर्ते नाटो इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हो।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत और पनामा ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों?

- भारत और पनामा ने 09 मई, 2018 को राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धाराकों को वीजा में छूट दिए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये, इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन समझौते पर पनामा शहर में उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू और पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वेरेला रॉड्रिग्स की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू की ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू जैसे तीन देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने हेतु उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा का यह दूसरा चरण था।

समझौते के मुख्य बिंदु

- वैंकेया नायडू ने पनामा द्वारा फाल्कन नीतियों में भारत को शामिल करने के लिए पनामा की सराहना की।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- उन्होंने कहा कि भारत और पनामा में दो जैव-विविधता केंद्र स्थापित किये जायेंगे जिनकी लागता 10 मिलियन डॉलर से 15 मिलियन डॉलर तक होगी।
- दोनों देश कर जानकारी, आर्थिक सहयोग, वायु सेवाओं, पारंपरिक दवाओं, संस्कृति और अंतरिक्ष में सहयोग को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
- पनामा मानवाधिकार परिषद् (एच.आर.सी.) के लिए भारत को 2019-2021 तक बतौर सदस्य चुने जाने के लिए समर्थन देने पर भी सहमत हुआ।
- संयुक्त वक्तव्य के रूप में दोनों ही देश आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु संकल्पित रहे।

यात्रा का उद्देश्य

- उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा तीन लैटिन अमेरिकी देशों-ग्वाटेमाला, पनामा एवं पेरू की यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में मधुरता लाना भी इस यात्रा का उद्देश्य था।

स्रोत: पी.आई.बी.

आयरलैड में जनमत संग्रह से 'गर्भपात' पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया

चर्चा में क्यों?

- आयरलैंड में जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है, यह जनमत संग्रह गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर किया गया था।
- आयरिश लोगों ने जनमत संग्रह कर 35 साल पूराने गर्भपात प्रतिबंध कानून के खिलाफ वोट देकर एतिहासिक जीत हासिल की है। गर्भपात से प्रतिबंध हटाने के पक्ष में मतदान को प्रेरित करने के लिए आयरलैंड में काफी दिनों से 'यस कैंपेन' चलाया जा रहा था।

मुख्य तथ्य:

- अयरलैंड में गर्भपात पर प्रतिबंध के प्रस्ताव के विरोध में हुए जनमत संग्रह में दो तिहाई लोगों ने मतदान किया है।
- मतदान को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस जनमत संग्रह के बाद यहां पर गर्भपात पर लगे बैन को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।
- जनमत संग्रह में 66.4 प्रतिशत ने इसके लिाफ वोट कर इसे संविधान से ही हटाने की मांग की है।
- आयरलैंड में इस समय गर्भपात की अनुमति सिर्फ माँ और शिशु की जान को खतरा होने पर ही है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आयरिश कानून क्या है?

- ऑफेंश अगेंस्ट द सर्सन एक्ट 1861 के मुताबिक गर्भपात पर रोक है। वर्ष 1983 में हुए आठवें संशोधन के मुताबिक गर्भपात कराने पर सजा का प्रावधान किया गया।
- इस आयरिश देश में गर्भ को खत्म करने पर 14 वर्ष तक की सजा का नियम है। आयरलैंड में वर्ष 1983 से अब तक 170,000 आयरिश महिलाएं गर्भपात के लिए विदेश जा चुकी है।
- इस बैन को खत्म करने के पक्ष में डबलिन की सड़कों पर लोग कैंपेन के स्लोगन के साथ टी-शर्ट पहनकर मार्च किया था।

पृष्ठभूमि:

- दरअसल इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह के पीछे एक भारतीय महिला रही थी। भारतीय मूल की सविता हलप्पनवार पेशे से डेंटिस्ट थीं। वर्ष 2012 में जब सविता को पता चला कि गर्भ में ही उनका बच्चा मर गया है। तो गर्भपता की इजाजत मांगी लेकिन आयरलैंड के कड़े कैथोलिक कानून के चलते उन्हें गर्भपात कराने की इजाजत नहीं मिली और इस कारण उनकी मौत हो गई।
- इसके बाद ही माँ की जिंदगी खतरे में होन पर गर्भपात की मंजूरी के लिए वर्ष 2013 में इसका कानून में बदलाव किया गया था।
- इस कानून को लेकर इस आयरिश देश में समय-समय पर विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं, लेकिन अभारतीय मूल की सविता की मौत के बाद ये प्रदर्शन और तेज हो गए, यहीं कारण रहा कि लोगों ने इस सख्त कानून के खिलाफ वोट किया।

आयरलैंड

- आयरलैंड पारंपरिक रूप से यूरोप के सबसे धार्मिक देशों में से एक है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर डबलिन है, जो द्ववीय के पूर्वी भाग में स्थित है, और जिसका महानगरीय क्षेत्र देश के 4.75 मिलियन निवासियों में से एक तिहाई का घर है, आयरलैंड की मूल, जो पारम्परिक संस्कृति है, वह अब गाँवों तक ही सीमित रह गयी है, आयरिश भाषा इस देश की मातृभाषा हैं और अँग्रेजी को सरकारी तौर पर दूसरी भाषा का स्थान प्राप्त है, आयरलैड की पब संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
- आयरलैंड में शिक्षा प्राइमरी, सेकेण्डरी और हाइयर तीन स्तरों पर निधारित की गई है। पिछले कुछ वर्षो में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है, आयरलैंड मं संग्रहालय और कला दीर्घाएँ बड़ी संख्या में है, मुख्यत: गर्मियों के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में संगीत और कला से सम्बंधित कई कार्यक्रम व्यवस्थित किए जाते है।

स्रोत: द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत ने चीन में अपना दूसरा आई.टी कॉरिडोर आरंभ किया

चर्चा में क्यों?

- भारत ने देश की बढ़ती सॉफ्टवेयर मार्केट का लाभ लेने हेतु 27 मई, 2018 को चीन में दूसरा आई.टी. कॉरिडोर आरंभ किया।
- इस आई.टी. कॉरिडोर का नाम, डिजिटल संयुक्त अवसर प्लाजा प्लेटफार्म (SIDCOP) है, इसकी स्थापना चीन के गुइयांग शहर में नेशनल एसोसिएशन ऑफ, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कम्पनीज (NASSCOM) द्वारा की गई है, उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय आई.टी. कम्पनियों को वृहद चीनी बाजार में सहज पहुंच दिलवाना है।

मुख्य तथ्य:

- इस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के दौरान छह मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हुए, इस समझौते पर भारतीय सेवा प्रदाताओं एवं चीनी उपभोक्ताओं की ओर से चीन के गुइयांग के जगर निगम द्वारा हस्ताक्षर किये गये।
- SIDCOP का जुलाई 2019 में आरंभ किया जायेगा, अभी इसे बतौर पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है।
- नैसकॉम ने पहला SIDCOP प्लेटफॉर्म चीन के बंदरगाह शहर डालियाअन में दिसंबर, 2017 में आरंभ किया था। यह चीन में भारत का पहला आई.टी. हब हैं।
- डालिआन आई.टी. कॉरिडोर का शुभारंभ औपचारिक रूप से कुछ समय पूर्व ही किया गया है।
- डालिआन कॉरिडोर का फोकस आईओटी (इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) था, जबकि गुइयांग में कॉरिडोर का फोकस आने वाले डाटा पर होगा।
- इस लॉन्च कार्यक्रम में भारत और चीन ओर से 350 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया।

  इस पहल को चीन के अन्य शहरो में भी ले जाया जायेगा।

महत्व

- इस पहल से भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियां तथा चीनी हार्डवयेर कम्पनियां साथ मिलकर काम कर सेंगी। इसके अलावा दोनों देशों में ऑटोमेशन, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) एवं अन्य उभरते आईटी क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकेगा, इससे चीनी कम्पनियों की आवश्यकताओं की भारतीय आई.टी. सर्विस प्रदाताओं द्वारा पूर्ति हो सकेगी।

पृष्ठभूमि

- चीन में भारत की आई.टी. कम्पनियों की बड़ी मात्रा में मौजूदगरी है। इसमें डालियन में बनाए गसे आई.टी. कॉरिडोर से छोटी एवं मध्यम भारतीय आई.टी. कम्पनियों को बढ़ावा मिल सकेगा।
- भारत के लिए, चीन के आई.टी. बाजार में पहुंच बनाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन का आई.टी. बाजार लगभग 493 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, इसमें विकास के अभी और आसार हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत कई वर्षों से चीन में भारतीय फार्मा कम्पनियों एवं आई.टी. कम्पनियों की पहुंच बनाने के लिए आग्रह करता रहा है ताकि दोनों देशों के बीच का व्यापार घाटा कम किया जा सके।
- चीन के 10 शहरों में भारत की विभिन्न आई.टी. कम्पनियां कार्यरत हैं जिनमं लगभग 25,000 लोग कार्यरत हैं।

स्रोतः इकोनॉमिक टाइम्स

भारत और नीदरलैंड के मध्य 50 समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दो दिवसीय भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट (Mark Rutte) ने 24 मई, 2018 को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सीईओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
- नीदरलैंड अब तक भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है। सी.ई.ओ. कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों देशों द्वारा आर्थिक एवं द्वविपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

भारत-नीदरलैंड समझौतों के मुख्य बिंदु

- नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आई.एस.स.) के फ्रेमवर्क समझाते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देशों के संबंधित संस्थानों ने हिंडन बेसिन में ठोस अपशिष्ट और जल की 'वेस्ट टू वेल्थ' परियोजनाक लिए हाथ मिलाया है।
- कानपुर व उन्नाव के चमड़ा उद्योग में सहयोग के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों अपनाने व उत्तर प्रदेश के गन्ना उद्योग में बेहतरीन कृषि उपयोग के जरिए जल के संरक्षण हेतु किये जाने वाले उपायों पर भी समझौता किया गया।
- दोनों पक्ष स्वच्छ गंगा अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जून, 2017 में हस्ताक्षर किए गए जल प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) के तहत सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
- भारत और नीदरलैंड के लोगों के बीच संपर्क एवं व्यापारिक आदान प्रदान को आसान बानाने के लिए वीजा नियमों को जचीला बनाने की सहमति व्यक्त की।
- नीदरलैंड एवं भारत ने स्मार्ट सिटी, नॉलेज संस्थानों, हाईटेक आईटी एवं अंतरिक्ष, जीवविज्ञान एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दस करारों पर हस्ताक्षर किये।
- कृषि एवं ाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, जल प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, जीव विज्ञान व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ अन्य में सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं की पहचान की गई।
- दोनों नेताओं ने बेंगलूरु में डच महावाणिज्य दूतावास खोले जाने का स्वागत किया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारत और नीदरलैंड ने वैश्वीकरण को सुनिश्चित करने, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ऊर्जा सुरक्षा, मानवाधिकार, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण रोकने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

भारत-नीदरलैंड संबंध

- भारत और नीदरलैंड के मध्य लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों देश व्यापारिक ओर वाणिज्यिक मुद्दों पर एक-दूसरे का सहयोग करते रहे हैं, विदेश मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत और नीदरलैंड के बीच (अप्रैल, 2018-फरवरी, 2018) 7.621 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, नीदरलैंड में 2,35,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है, रूट के दौरे से भारत व नीदरलैंड के बीच आर्थिक व राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

स्रोतः पी.आई.बी.

प्रधानमंत्री मोदी और व्लांदिमीर पुतिन के बीच अनौपचारिक शिर बैठक

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सोची शहर में 21 मई, 2018 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक शिर बैठक की इस दौरान पुतिन ने कहा कि भारत-रूस के संबंध काफी मजबूत हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी वार्ता से दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आएगी।
- भारत और रूस की यह दोस्ती बहुत पुरानी है और आज की यह मुलाकात कई लिहाज से खास है, क्योंकि पुतिन ने चौथी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने के बाद पीएम मोदी को रूस की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया है।

मुख्य तथ्यः

- दोनों नेताओं के बीच ईरान एटमी डील से अमेरिका के पीछे हटने के फैसले का आर्थिक असर, अफगानिस्तान और सीरिया के हालात, आतंकवाद के खतरे और आगामी शंघाई सहयोग संगठन एवं ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित मुद्दों पर बात हुई।
- वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा अनौपचारिक शिखर बैठक में मोदी-पुतिन के बीच आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने के तरीके पर बातचीत हुई।

हथियार सौदे पर बातः

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रूस यात्रा के दौरान सबसे अहम मुद्रा रूस के साथ हथियार सौदे का हैं। भारत और रूस के बीच करीब 40 हजार करोड़ रुपये (करीब 12 अरब डॉलर) आर्म्स डील हुई थी, लेकिन रूसी सैन्य निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध के चलते यह डील अभी तक रुका हुआ है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

शांतिपूर्ण उद्देश्यः

- रूस ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भारत की जरूरत को माना है। दिसंबर, 2014 में , डिपार्टमेंट ऑफ ऐटमिक एनर्जी और रूस के रोसाटम ने भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर सहयोग बढ़ाने के लिए स्ट्रैटजिक विजन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की मदद से ही बनाया जा रहा है।
- शंघाइ सहयोग संगठन में आठ देश सदस्य है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है भारत और पाकिस्तान पिछले वर्ष इस संगठन में शामिल हुए भारत को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थाई सदस्यता दिलाने में रूस ने अहम भूमिका निभाई है।

भारत और रूस संबंधः

- भारत और रूस की यह दोस्ती बहुत पुरानी है। रूस भारत को मजबूत और मुश्किल समय का दोस्त रहा है। दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते का लंबा इतिहास रहा है।
- भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के सम्बंध बहुत अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ में मजबूत रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक, एवं राजनयिक सम्बंध रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोनों के सम्बंध पूर्ववत बने रहें।
- दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, राजनीति, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और आतंकवाद के लिाफ लड़ाई और स्पेस के क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग किया है।
- रूस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हुए अभी भी भारतीय बाजार में हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है रूस ही इकलौता ऐसा देश है जो भारत की भविष्य की जरूरतों पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स (सुखोई PAK-FA), न्यूक्लियर सब मैरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरा कर सकता हैं।
- दिसंबर, 2014 में, दोनों देशों ने वर्ष 2025 तक व्यापार बढ़ाकर 30 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा था। स्पेस एनर्जी-भारत-रूस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में चार दशकों से साथ काम कर रहे हैं।
- 2015 में भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की लॉन्चिंग को 40 साल पूरे हुए थे। इस सैटेलाइट का लॉन्च वेहिकल रूसी सोयूज ही था। दोनों देश वर्तमान में मानव स्पेस फ्लाइट की संभावना पर काम कर रहे हैं।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

क्लैंपडाउंस एंड करेज-साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18

चर्चा में क्यों?

- यूनेस्को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, 2017-18 जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व भर में इंटरनेट सेवा बंद करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें चिंता जाहिर की इगई कि इस प्रकार की घटनांए प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खता हैं।
- यूनेस्को की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में मई, 2017 से अप्रैल, 2018 के बीच इंटरनेट बंद होने की कम से कम 97 घटनाएं हुई जिसमें अकेले भारत में ऐसे 82 मामले सामने आए।

यूनेस्को रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट यूनेस्को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा जारी की गई जिसका शीर्षक है। क्लैंपडाउंस करेज-साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18
- रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद होने की 12 घटनाएं हुई जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ऐसी एक-एक घटनाएं हुई हैं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में इंटरनेट बंद किये जाने के 10 मामले देखे गए, जबकि हरियाणा में 10 से कम मामले दर्ज किये गये।
- दार्जीलिंग में 45 दिनों के लिए राजनीतिक आंदोलन और विवाद के चलते इंटरनेट सेवा बंद की गई थी।
- बिहार के नवादा में सांप्रदायिक हिंसा के चलते 40 दिनों के लिए इन्टरनेट बंद था।
- जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए 31 दिनों तक इंटरनेट सेवा बदं की गई।
- जम्मू-कश्मीर में जुलाई, 2017 में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला होने पर 15 दिन के लिए इन्टरनेट सेवा बंद कर दी गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट सेवा बंद होन पर पत्रकारों का कार्य अवरुद्ध हुआ जिसमें वे अनुसंधान, जानकारी सत्यापन तथा पत्रकरिता के लिए आवश्यक संचार उपकरणों को उपयोग नहीं कर पाते।
- इन्टरनेट बंद होने पर पत्रकार अपना काम नहीं कर पाते और न ही सही जगह खबर पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा नागरकि भी जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह मानवाधिकार के लिए खतरा है और लोगों के जानकारी हासिल करेन के अधिकार के विरुद्ध है।
- रिपोर्ट के अनुसार इन्टरनेट बंद करना सेंसरशिप का एक उपकरण बन चुका है जिसे सरकारें अपने हित के लिए उपयोग करती हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

यूनेस्को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नर्जलिस्ट के उद्देश्य

- प्रेस और उनके वैध व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करें, और इस पेशे के मानकों को संरक्षित करना है।
- जब भी प्रेस और पत्रकारों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर खतरा होता है तो कार्रवाई करना।
- संबंधित एजेंसियों से विभिन्न देशों में पत्रकरों की स्थिति की जानकारी लेना एवं आवश्यक कदम उठाना।
- पत्रकरों को ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण तथा कार्यक्षेत्र में सुधार हेतु प्रशिक्षण देना।
- इसकी स्थापना 1926 में की गई थी इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

स्रोतः द हिंदू

ELITE IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास

भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार और विश्व बैंक के बीच 31 मई, 2018 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ।

मुख्य तथ्य

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत, 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं, जिसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जाएगा।
- परियोजना के लिए कर्ज समझौते पर ग्रामीण विभाग में संयुक्त सचिव (आरसी) अलका उपाध्याय की मौजूदगी में भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की तरफ से कंट्री निदेशक (भारत) जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किये।

महत्व:

- पीएमजीएसवाई से पहचान, डिजाइन, निगरानी और निर्माण, समुदायों विशेषकर महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में व्यापक बदलाव संभव हुआ है।
- अतिरक्ति वित्तपोषण से हरित प्रौद्योगिकी और कम कार्बन वाली डिजाइन व निर्माण की जलवायु अनुकूल तकनीकों से निर्माण की प्रोद्ययोगिकी में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
- यह ग्रामीण समुदायों की आर्थिक अवसरों और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

पी.एम.जी.एस.वाई. में विश्व बैंक की भूमिका

- विश्व बैंक वर्ष 2004 से ही पी.एम.जी.एस.वाई. को सहयोग दे रहा है।
- अभी तक इसके तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और पहाड़ी राज्यों में 180 करोड़ डॉलर के कर्ज के माध्यम से निवेश किया जा चुका है।
- इसके अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 लाख लोगों को फायदा हुआ है।

उद्देश्य:

- इस अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाई और बैंक की भागीदारी से महत वित्तपोषण के अलावा हरित तकनीक, कम कार्बन वाली डिजाइन और नई तकनीकों के इस्तेमाल से हरित और जलवायु अनुकूल निर्माण के माध्यम से ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

यह निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जाएगा।

- बाढ़, जलभराव, बादल फटने, तूफान, भूस्खलन, खराब जल निकासी, अत्यधिक कटाव, भारी बारिश और ऊंचे तापमान से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान क लिए डिजाइन की प्रक्रिया के दौरान जलवायु जोखिम आकलन करना हैं।
- पर्यावरण अनुकूल सड़कों के डिजाइन और नई तकनीकों के उपयोग जिनमें टूटे हुए पत्थरों के स्थान पर स्थानीय सामग्री और रेत, स्थानीय मिट्टी, फ्लाई ऐश, ब्रिक क्लिन वेस्ट और अन्य सामग्रियों जैसे औद्योगिक उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है।
- पहाड़ी इलाकों की सड़कों में कटाई की सामग्री का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और उनके निस्तारण की समस्या का समाधान क लिए जैव अभियांत्रिकी उपयों के इस्तेमाल, निकासी में सुधार और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए अन्य उपाय और पर्याप्त ढाल सुरक्षा उपलब्ध कराना हैं।
- जल की सुगम निकासरी हेतु पर्याप्त जलमार्गों और सबमर्सिबल सड़कों, कंकरीट ब्लॉक पेवमेंट्स के इस्तेमाल, जब निकासी में सुधार के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष रखरखाव शामिल है।
- पुलियों का निर्माण, जो भूकंप और पानी के दबाव की स्थिति में टिके रहने में सक्षम होते हैं।
- इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता से निर्माण और रखरखाव मे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करके लिंग भेद भी कम किया जाएगा। पिछली परियोजना में उत्तराखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर पी.एम.जी.एस. वा.ई. सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से समुदाय आधारित रखरखाव अनुबंध की योजना बनाई गई थी। एस.एच.जी. द्वारा नियंत्रित रखरखाव अनुबंधों को 5 राज्यों की 500 किलोमीटर सड़कों तक बढ़ाया जाएगा।

स्रोत: पी.आई.बी.

विदेश से धन भेजने के मामले में भारतीय दुनिया में सबसे आगे

चर्चा में क्यों?

- भारत विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, देश के प्रवासी कामगारों ने वर्ष 2017 में 69 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश से भारत भेजे।
- रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में विदेश से 256 अरब डॉलर भेजे गए यह रिपोर्ट रेमिटस्कोप-रेमिटेंस मार्केट्स एंड अपॉच्यूनिटीज-एशिया एंड द पैसिफिक द्वारा प्रकाशित की गई।

विदेश से धन भेजने के मामले में विभिन्न देशों की सूची:

- वर्ष 2017 में भारत (69 अरब डॉलर), चीन (64 अरब डॉलर) और फिलीपीन (33 अरब डॉलर) में क्रमश: विदेश से सबसे ज्यादा रकम भेजी गई।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- पाकिस्तान (20 अरब डॉलर) और वियतनाम (14 अरब डॉलर) भी विदेश से बड़ी रकम प्राप्त करने वाले टॉप 10 देशों में शुमार हैं।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भेजी जाने वाली रकम:

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भेजी जाने वाली रकम का 70 फीसद क्षेत्र के बाहर से आता है और उसमें भी खास तौर पर खाड़ी देशों से 32 फीसदी, उत्तर अमेरिका से 26 फीसदी और यूरोप से 12 फीसदी आता हैं।

सबसे ज्यादा मनीऑर्डर:

- इससे पहले वर्ष 2016 में भारत को सबसे ज्यादा मनीऑर्डर मिला था हालांकि, इस स्त्रोत से भारत की कमाई सिर्फ एक अरब डॉलर ही हुई थी।
- इससे पहले वर्ष 2009 में इस आंकड़े में गिरावट देखी गई थी। वर्ष 2014 में भी भारतीयों ने 70 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि स्वदेश भेजी थी।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2030 तक विकासशील देशों को विदेश से भेजी जाने वाली रकम 6000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- इसमें से आधी रकम एशिया प्रशांत क्षेत्र में आएगी जो अक्सर बेहद छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचती है।
- इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफडी) के अनुसार वर्ष 2017 में प्रवासी कामगारों ने अपने परिवारों को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 256 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम भेजी।

स्रोतः द हिंदू

❒ भारत ने विश्व बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया

चर्चा में क्यों?

- भारत ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ने मजबूत करने के लिए 29 मई 2018 को विश्व बैंक के साथ 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया।

मुख्य तथ्य

- इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (एफबी और एडीबी) समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यकारी कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किये।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- कार्यान्वयन इकाई समझौते पर राजस्थान सरकार की ओर से वित्त (बजट) सचिव और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर ने हस्ताक्षर किये।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में राजस्व प्रशासन में बेहतर बजट निष्पादन, बढ़ी जवाबदेही और अधिक दक्षता में योगदान करना है।
- यह परियोजना 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की है, जिसमें से 21.7 मिलियन अमरीकी डॉलर विश्व बैंक से और शेष राशि राज्य बजट से ली जाएगी।
- इस परियोजना की अवधि 5 साल है।
- परियोजना में अन्य कार्यों के अलावा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यय एवं राजस्व प्रणाली को सुदढ़ करना और परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

विश्व बैंक:

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पांच अन्तर राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में हैं
- विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थ व्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है।
- विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है।

स्रोतः पीआईबी

मुद्रा योजना को बढ़ावा देने हेतु 40 कम्पनियों के साथ समझौता

चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने मुद्रा योजना को बढ़ावा देने के लिए तथा छोटे उद्यमियों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए देश की 40 बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार फ्लिपकार्ट, स्विगी, पतंजलि और अमूल सहित यह सभी इकाइयां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जा सकने लायक लोगों की पहचान करने के लिए मंत्रालय 23 जून को मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, ताकि ज्यादा लोगों को इसके तहत ऋण आवंटित किया जा सके।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

समझौते में शामिल कम्पनियां

- फाइनेंशियल सर्विसेस डिपार्टमेंट ने जिन कंपनियों के साथ समझौता किया है, उनमें मेक माई ट्रिप, जोमैटो, मेरु कैब, मुथूट, एडलवाइस, अमेजन, ओला, बिग बास्केट, कार ऑन रेंट और हबीब सैलून भी शामिल हैं।
- इसके साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजन, उबर, ओला, ओयो, अमूल, पंतजलि और जोमैटो जैसे कंपनियों की रिटेल फ्रेंचाइजी/ट्रांसपोर्ट सॉल्युशंस/स्प्लायर्स को मुद्रा स्कीम के तहत् 10 लाख रुपए तक लोन देने के मसले पर भी विचार किया जाएगा।

समझौते के मुख्य बिंदु

- यह कंपनियों ऐसे लोगों की पहचान करेंगी, जिन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की जरूरत है। उनकी सहमति के बाद इस योजना के तहत् लोन दिया जायेगा।
- मुद्रा योजना के तहत् लोन लेने के इच्छुक लोग बैंक से संपर्क करते हैं, लेकिन इस पहल फाइनेंशियल सर्विसेस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों तक स्वयं पहुंचेगा।
- जिन लोगों को अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है लेकिन उन्होंने बैंक से संपर्क नहीं किया है उन्हें स्वयं संपर्क किया जायेगा।
- पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने मुद्रा योजना के तहत् 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि बीते तीन साल के दौरान 5.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है।

मुद्रा योजना क्या है?

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत् कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय आरम्भ करना चाहता है उसे सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण प्राप्त हो सकता है। इसमें दिए जाने वाले ऋण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण यह मूल रूप देश के गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यापारियों के वित्तीय पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया उपक्रम है।
- शिशु श्रेणी यह श्रेणी व्यापार के शुरुआती दौर की श्रेणी है। वे सभी व्यापार जो की अभी–अभी शुरू हुए है और लोन के लिए देश रहे है इसे श्रणी में आते है। इस श्रेणी में आने वाले सभी माइक्रो यूनिट्स के लिए 50,000 रुपये तक का लोन दिया जायेगा। शिशु श्रेणी के लिए ब्याज दर 10 से 12% तक की रेंज में है।

  किशोर श्रेणी इस श्रेणी के अंतर्गत कारोबार आरंभ होने तथा उसके बढ़ने के दौरान का समय आता है। इसे श्रेणी के अंतर्गत आते है। इस श्रेणी के व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि वित्तीय आवश्यकता है तो कारोबारी को 10,00,000 रूपये तक का ऋण दिया जा सकता है। तरूण श्रेणी के लिए ब्याज दर 16% आरंभ होती है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

व्यापार आशावाद सूचकांक

चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2018 की पहली तिमाही में ग्रांट थॉर्नटन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट (IBR) के एक भाग के रूप में जारी वैश्विक व्यापार आशावाद सूचकांक में भारत छठे स्थान पर रहा। भारत चार वर्ष तक इस सूची में शीर्ष पर रहा है लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा छठे स्थान पर रहा।
- यह रिपोर्ट 37 अर्थव्यवस्थाओं में 2,500 व्यवसायों के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में शीर्ष पांच राष्ट्र ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड और अमेरिका हैं।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट में 89 के स्कोर वाले भारत को इंडेक्स में छठे स्थान पर स्थान मिला।
- भारत चार साल तक चार्ट में सबसे ऊपर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बिगड़ गया।
- भारत का व्यापार आशावाद अन्य मानकों में जैसे राजस्व, कीमत, लाभप्रदता, रोजगार और निर्यात अपेक्षाओं सहित बिक्री आदि में दर्शाया जाता है।
- भारत द्वारा वैश्विक आर्थिक महाशक्तियों के साथ संबंध सुधारने हेतु किये जा रहे प्रयासों से छठा स्थान मिला अन्यथा रैंकिंग इससे भी नीचे जा सकती थी।
- भारतीय व्यापार को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारणों में लाल-फीताशाही, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता, आईसीटी बुनियादी ढांचे की कमी और पूँजी की कमी को सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में देखा गया।
- वर्ल्ड बैंक की व्यापार करने में आसानी की सूची में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन इन आधारभूत लेकिन महत्वपूर्ण बाधाओं को पार करने में अभी भी असफल रहा है।

ग्रांट थॉर्नटन

- ग्रांट थॉर्नटन एक भारतीय संगठन है जो व्यापारिक परिदृश्यों को समझने के लिए सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट्स जारी करती है जिससे व्यापारिक लाभ के साथ-साथ वास्तविक स्थिति का भी पता लगता है। यह एक निजी फर्म है जो कम्पनियों को एडवाइजरी, कॉरपोरेट फाइनेंस, व्यापार के जोखिम के प्रबंधन, रणनीतिक योजनाओं आदि में सहायता प्रदान करती है, इसका मुख्यालय हरियाणा स्थित गुडगांव में है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं स्वास्थ्य

डब्ल्यूएचओ ने पहली आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची जारी की

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आम रोगों और प्राथमिकता वाले रोगों के निदान के लिए आवश्यक परीक्षणों की एक सूची आवश्यक परीक्षणों की एक सूची आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची (essential diagonstic list) प्रकाशित की है।
- यह डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई इस तरह की पहली सूची है।
- सूची में विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक्स के लिए लागू डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों की जानकारी भी शामिल है और बताया गया है कि किसी विशेष श्रेणी में डब्ल्यूएचओ प्रीक्वॉलीफाइड उत्पाद उपलब्ध हैं या नहीं।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य डायगनोस्टिक सेवाओं तक पहुंचने में लोगों की अक्षमता (inablility) को दूर करना है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सही उपचार प्राप्त हो सके। लोगों तक निदान सेवाओं की पहुंच नहीं होना एक समस्या है जिसके कारण उन्हें सही उपचार नहीं मिल पाता। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- यह सूची डब्ल्यूएचओ की आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) के समान है, जिसे 1977 से हर दो साल में बदला जाता है। यह सूची महत्वपूर्ण दवाओं के खरीद निर्णय लेने के लिए दुनिया भर के स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग की जाती है।

घोषणा की मुख्य विशेषताएं

- आवश्यक निदान परीक्षण में रक्त और मूत्र परीक्षण समेत 58 परीक्षण शामिल हैं।
- अन्य 55 परीक्षणों में एचआईवी, टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी आर सौ सी आदि का पता लगाने और जांच करने को शामिल किया गया है।
- आवश्यक निदान परीक्षण सूची में रक्त जांच और मूत्र परीक्षण आदि पर जोर दिया गया है।
- प्राथमिक बीमारियां जैसे ट्यूबरक्युलोसिस, मलेरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस और मानव पेपिलोमावायरस की पहचान निदान और निगरानी हेतु 55 परीक्षण होते हैं।
- इस संबंध में डब्ल्यूएचओ नियमित आधार पर सूची अपडेट करेगा और अगले संस्करण में श्रेणियों (categories) को जोड़ने हेतु आवेदन जारी करेगा।
- विश्व निकाय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 46 फीसदी वयस्क लोगों के रोग का निदान नहीं हो पाता इस स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताओं

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

का खतरा रहता है और उन्हें सेहत पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी जानकारी में कहा गया कि एचआईवी और टीबी जैसे संक्रामक रोगों का विलंब से निदान होने से इन रोगों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है और उनका उपचार कठिन हो जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इससे पूर्व मौजूद स्वास्थ्य संगठन के स्थान पर इसे लाया गया था जो लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी थी।

स्रोत : द हिंदू

स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भारत 145वें स्थान पर: लांसेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लांसेट द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में 145 नंबर पर है। लांसेट द्वारा कुल 195 देशों पर किये गये इस सर्वेक्षण में भारत 145वें स्थान पर है। भारत इस सर्वेक्षण में चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान से भी पीछे है।
- द ग्लोबल बर्डन ऑफ डीसीज स्टडी द्वारा कहा गया है कि वर्ष 1990 की तुलना में प्रत्येक भारतीय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भारत में अभी भी चुनौती है। वर्ष 2016 के अध्ययन में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध ता तथा गुणवत्ता की रैंकिंग 41.2 थी जो कि 1990 (24.7) की तुलना में काफी बेहतर है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- भारत का स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्ता रैंकिंग में वर्ष 2000 से 2016 तक तेजी से सुधार देखा गया।
- इस दौरान भारत के उच्चतम और निम्नतम स्कोर में भारी अंतर देखा गया। वर्ष 1990 में यह अंतर 23.4 था जबकि 2016 में यह अंतर बढ़कर 30.8 हो गया।
- रिपोर्ट के अनुसार गोवा और केरल के वर्ष 2016 में सबसे अधिक (60 से अधिक) अंक थे जबकि असम और उत्तर प्रदेश के सबसे कम (40 कम) अंक थे।
- भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें चीन (48), श्रीलंका (71), बांग्लादेश (133)व भूटान (134) देश शामिल हैं।
- सूची के अनुसार भारत नेपाल (149), पाकिस्तान (154) और अफगानिस्तान (191) से बेहतर स्थिति में है।

कम रैंकिंग के कारण

- अध्ययन के अनुसार, भारत में तपेदिक के मामलों, हृदय रोग, स्ट्रोक, टेस्टिकुलर कैंसर, कोलन कैंसर और क्रोनिक किडनी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

रोग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है जिसके चलते भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रही है। चीन और भारत जैसे देशों में सामाजिक असमानताओं के कारण भी यह रैंकिंग प्रभावित होती है जबकि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में स्थानीय स्तर पर अंतर देखने को मिलते हैं।

सबसे अधिक रैंकिंग वाले 5 देश	5 सबसे कम रैंकिंग वाले 5 देश
1. आइसलैंड (97.1)	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (18.6)
2. नॉर्वे (96.6)	सोमालिया (19.0)
3. नीदरलैंड (96.1)	गुएना-बिसाऊ (23.4)
4. लक्सम्बर्ग (96.0)	चाड (25.4)
5. फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया (95.9)	अफगानिस्तान (25.9)

स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने सिंगापुर में रूपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 31 मई 2018 को सिंगापुर में रूपे कार्ड, भीम ओर एसबीआई ऐप लॉन्च किया।

मुख्य तथ्य

- भारत की रूपे डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुर की 33 साल पुरानी नेटवर्क फोर इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर्स (एनईटीएस) से जोड़ा गया है।
- रूपे के सभी उपभोक्ता सिंगापुर में उन सभी जगहों पर भुगतान पर पाएंगे जहां एनईटीएस स्वीकार्य है।
- इसी तरह सिंगापुर एनईटीएस के धारक भारत में एनपीसीआई ई-कामर्स मर्चेंट वेबसाइट पर आनलाइन खरीद के लिए 28 लाख रूपे प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल कर पाएंगे।
- इस पहल से जहां रूपे भुगतान प्रणाली का अंतरराष्ट्रीयकरण शुरू होगा वहीं इससे अरबों डॉलर के लेनदेन का मार्ग प्रशस्त होगा।

भीप ऐप

- भीप ऐप वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरम्भ किया गया एक मोबाइल ऐप है।
- इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए 30 दिसम्बर 2016 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम एप को लॉन्च किया था।
- भीम का मतलब भारत इंटरफेस ऑफ मनी ऐप हैं।

रूपे कार्ड

- रूपे कार्ड भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है।
- इसे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है।
- अभी देश में भुगतान के लिए वीजा और मास्ट कार्ड के डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रचलन में हैं।
- ये कार्ड विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित है रूपे कार्ड को अप्रैल 2011 में विकसित गया था।
- इसे भारती राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने विकसित किया है। एनपीसीआई ने रूपे सेवा को अप्रैल 2013 में ही शुरू कर दिया था जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह कार्य रूप देने में सामान्यत: पाँच से सात वर्ष लग जाते हैं।
- रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है।

स्रोत: द हिंदू

3डी प्रिंटेड कॉर्निया विकसित

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने पहली बार 3डी प्रिंटेड मानव आँख का कॉर्निया बनाया है। इससे नेत्रदान करने वालों की कमी दूर करने और दृष्टि बाधित लाखों लोगों को रोशनी लौटाने में मदद मिल सकती है।

मुख्य तथ्य

- यह खोज एक्सपेरिमेंटल आई रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है इसमें बताया गया है कि किस तरह से किसी स्वस्थ दानकर्ता के कॉर्निया की स्टेम सेल को एकसाथ मिलकर दृष्टिहीनता का समाधान निकाला जा सकता है।
- इस पूरी प्रक्रिया को थ्री डी बायो प्रिंटर के माध्यम से बताया गया है।
- मानव शरीर में आंखों की बाहरी परत के रूप में कॉर्निया दृष्टि को फोकस करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि विज्ञान जगत में यह एक बड़ी समस्या रही है कि प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- विश्वभर में लगभग एक करोड़ लोगों को कॉर्निया से संबद्ध दृष्टिहीनता दूर करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत होती है।
- आंखों से संबंधित संक्रामक रोग जैसे कि ट्रैकोमा के कारण लोगों को कॉर्निया को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा जलने, जख्म, खरोंच या किसी बीमारी के चलते कॉर्निया के क्षतिग्रस्त होने के कारण करीब 50 लाख लोग पूरी तरह से दृष्टिहीनता के शिकार हो जाते हैं।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारत में दृष्टिहीनता और खोज का महत्व

- भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1976 में पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 2020 तक दृष्टिहीनों की संख्या 0.3 प्रतिशत करने के लक्ष्य से शुरू किया गया।
- वर्ष 2006-07 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता 2001-2002 के 1.1 से 2006-07 में 1 प्रतिशत रह गई है।
- इसे तहत लाभार्थी मोतियाबिंद, अपवर्तक त्रुटि, कॉर्निया अंधत्व जैसे अंधेपन के मुख्य कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उसका इलाज करा सकते हैं।
- 3डी कॉर्निया की खोज भारत के लिए फिलहाल महंगी साबित हो सकती है लेकिन इसके फायदों से इंकार नहीं किया जा सकता।
- यदि भारत में सरकारी सहायता से इस तकनीक को लॉन्च किया जाता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा हो सकता है।

स्रोतः द हिंदू

भारत-रूस के मध्य अत्याधुनिक एस-400 सिस्टम खरीदने हेतु समझौता

चर्चा में क्यों?

- भारत ने वायु सेना की आवश्यकताओं के लिए रूस से एस-400 ट्रंफ हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए कीमत संबंधी बातचीत पूरी कर ली है। यह खरीद समझौता लगभग 40,000 करोड़ रुपये में तय हुआ है।

मुख्य उद्देश्य

- इस सौदे को इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका एवं यूरोपीय देशों द्वारा घोषणा की गई थी कि रूस के रक्षा अथवा खुफिया प्रतिष्ठानों से लेन-देन करने वाले देशों और कंपनियों पर दंड लगाया जा सकता है।
- भारत विशेषतौर पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी चीन-भारत सीमा पर अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियां खरीदना चाहता है।
- एस-400 प्रणाली एस-300 का उन्नत संस्करण है अलमाज-एन्ट द्वारा उत्पादित यह मिसाइल प्रणाली रूस में साल 2007 से सेवा में है।
- गौरतलब है कि चीन ने भी रूस से यह मिसाइलें खरीदी हैं। एस-400 ट्रियंक एंटी मिसाइल सिस्टम से भारत को एक ऐसा कवच मिल जाएगा जो किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है।
- इस सिस्टम से भारत पर होने वाले परमाणु हमले का भी जवाब दिया जा सकेगा।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

एस-400 ट्रम्फ मिसाइल की विशेषताएं

- यह वायुगतिकीय यानी हवा में (एयरोडाइनिमिक) लक्ष्यों के लिए बनाई गई है जो 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मिसाइल को निशान बना सकती है।
- मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रफ्तार 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है जबकि इसके नवीनतम संस्करण में यह हाइपरसोनिक गति से ट्रेवल कर सकती है।
- एस-400 लगभग 10,000 फीट (30 किमी) की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। यह अमेरिका की एमआईएम-104 से दोगुनी गति से उड़ान भरती है। इसकी तैनाती में 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है।

स्रोतः द हिंदू

भारत-नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण- XIII उत्तराखंड में आरंभ

चर्चा में क्यों?

- भारतीय और नेपाल के सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के लिए भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण-XIII का आयोजन 30 मई से 12 जून तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है।
- इस युद्धाभ्यास में लगभग 300 भारतीय सैनिक एवं नेपाली सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं विगत में आयोजित विभिन्न काउन्टर इंसर्जेन्सी एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों के अनुरूप अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगी।

सूर्य किरण सैन्य अभ्यास

- सूर्य किरण एक छमाही सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास है जो बारी-बारी से भारत एवं नेपाल में आयोजित किया जाता है।
- भारतीय सेना द्वारा विभिन्न देशों के साथ आयोजित होने वाले सैन्य युद्धाभ्यासों के अपेक्षा नेपाल के साथ आयोजित होने वाला सूर्य किरण युद्धाभ्यास, इसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा है।
- इस सैन्य युद्धाभ्यास के मुख्य उद्देश्य नेपाल तथा भारतीय सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सफल संचालन के लिए दोनों देशों की सेना के बीच समन्वय विकास स्थापित करना है।

सूर्य किरण-XIII की विशेषताएं

- सूर्य किरण-XIII में आपदा प्रबन्धन सहित राहत एवं बचाव के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया जायेगा।
- इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यासों से दोनों देशों के बीच रक्षा समन्वय के साथ-साथ दृविपक्षीय संबंधों को बनाने में भी मदद मिलेगी।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसमें आतंकवाद विरोधी और जंगलों में होने वाले अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दोनों देशों के सैनिक मिलकर एक-दूसरे देश के नागरिकों की सहायता कर सकें, इसके लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- सूर्यकिरण-XIII के आयोजन के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के लड़ाकू उपकरणों, हथियारों, योजनाओं एवं रणनीतियों, विशेष तकनीकों, दुर्गम क्षेत्रों में आतकंवाद विरोधी अभियान चलाने से परिचित होंगे

स्रोतः द हिंदू

यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखा गया

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 30 मई 2018 को घोषणा की कि वे यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित कर के यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रख रहे हैं।

  इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को कम करना है।
- यह कदम अमेरिकी रणनीतिक सोच में भारत के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित (US Pacific Command) अमेरिकी प्रशांत कमान या पीएसीओएम को अब से इंडो-पैसिफिक कमांड के नाम से जाना जाएगा।
- अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के दौरान इस आशय की घोषणा की।
- कार्यक्रम के दौरान एडमिरल फिल डेविडसन ने यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर के रूप में हैरी हैरिस का स्थान लिया।

भारत पर प्रभाव

- यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखने से भारत को भी इसके कवर्ड क्षेत्र में रखा जायेगा।
- इसका परिणाम यह होगा कि चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को सामने लायेगा।
- इस कमांड में 3,75,000 से अधिक सैनिक कार्यरत हैं तथा भारतीय क्षेत्र में भारतीय सैन्य बल का सहयोग करने के लिए यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड मिलकर काम कर सकेगी।

यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड

- यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM, पहले USPACOM) संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों को एक एकीकृत लड़ाकू टुकड़ी है जो भारत-एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस क्षेत्र में होने वाले सैन्य ऑपरेशन के लिए इसी टुकडी को भेजा जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कमांड भी है क्योंकि यह लगभग 100 मिलियन स्क्वायर मली में फैले क्षेत्र की रक्षा का जिम्मा संभालती है।
- यूएस इंडो-फैसिफिक कमांड का कमांडर, अमेरिकी रक्षा मंत्री के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
- इस कमांड को अमेरिकी पैसिफिक सेना, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट, अमेरिकी पैसिफिक वायु सेना, अमेरिकी पैसिफिक समुद्री सेना, अमेरिकी सेना जपान, अमेरिकी सेना कोरिया विशेष संचालन कमांड कोरिया, और विश्व संचालन कमांड पैसिफिक द्वारा सहायता दी जाती है।

स्रोतः द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस-2018

चर्चा में क्यों?

- विश्व भर में 29 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर युद्ध से तबाह देशों और समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने कि दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं के कार्य की सराहना तथा सम्मान के लिए भिन्न भिन्न आयोजन दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं।

मुख्य तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस-2018 का विषय था संयुक्त राष्ट्र शांतिकर्मी: 70 साल की सेवा और बलिदान।
- यह दिवस वर्ष 1948 से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत 2,980 से अधिक शांति सैनिकों को संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है।
- यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था।

इस दिवस का मुख्य उद्देश्य :

- शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उन्हें सम्मान प्रदान करना।
- सभी पुरुष एवं महिला शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि देना एवं उनके कार्यो, जज्बे एवं समर्पण का सम्मान करना।

पृष्ठभूमि:

- इसे यूक्रेनी शांति स्थापना एसोसिएशन एवं यूक्रेन सरकार के आग्रह पर अपनाया गया।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 57/129 प्रस्ताव पारित कर के 11 दिसम्बर, 2002 को अपनाया गया।
- मई 29 की तिथि को इसलिए रखा गया है क्योंकि इस दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविजन आर्गेनाईजेशन (यूएनटीएसओ) को अरब-इसरायल युद्ध में शांति वार्ता की निगरानी रखने के लिए निर्धारित किया गया था।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने रक्षा बलों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 28 मई, 2018 को रक्षा बलों के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी हैं। यह बैठक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।
- डीएसी ने रक्षा बलों के लिए 6900 करोड़ से अधिक के उपकरण खरीद की स्वीकृति।
- स्वदेशीकरण को भारी प्रोत्साहन देते हुए और भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति को स्वीकार करते हुए रॉकेट लांचर के लिए थर्मल इमेजिंग (टीआई) नाइटसाइट्स की खरीद बाय Buy Indian आईडीडीकरण श्रेणी के अंतर्गत स्थापित भारतीय वेंडरों के माध्यम से की जाएगी।

उपयोग:

- इसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है और 84 एमएम रॉकेट लांचर के लिए टीआइ साइट का इस्तेमाल टुकड़ियों द्वारा दुश्मन के सक्रिय और स्थिर लक्षों पर सटीक निशाना साधने और पूरी तरह अंधकार के दौरान दुश्मन के बंकरों का विध्वंश करने में किया जाता है।
- यह साइट अपनी टुकड़ियों को शत्रुओं के टैंकों की खोज करने और पहचानने तथा रात के समय सैनिकों की गतिविधियों में सहायक होगा।
- यह छद्म रूप से छिपने और पनाह लेने में कमी लाएगा, क्योंकि रॉकेट लांचर के डिटेटचमेंट शत्रु के छिपे हुए स्थान का पता लगाने में सक्षम होंगे।

उपकरणों से संबंधित मुख्य तथ्य:

- डीएसी ने 'मेक II' उपश्रेणी के अंतर्गत एसयू-30 एमकेआई विमान के लिए लंबी दूरी की डुअल बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एंड ट्रैक सिस्टम (आईआरएसटी) के डिजाइन और विकास की स्वीकृति दी और बाद में बाय (इंडियन) श्रेणी के अंतर्गत 100 आईआरएसटी खरीद के लिए स्वीकृति दी।
- यह प्रणाली दिन और रात दोनों समय कार्य करेगी और विमानों की क्षमता में वृद्धि करेगी।
- इन स्वीकृतियों के साथ अकेले पिछले आठ महीनों में डीएसी ने पूरे उत्साह के साथ सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को आगे बढ़ाया है और स्वदेशीकरण पर बल दिया है।
- लगभग 43,844 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 32,253 करोड़ रुपये के उपकरण भारत में बनाए जाएंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी):

- देश की रक्षा एवं सुरक्षा में सुधार हेतु की जाने वाली खरीद और अधिग्रहण के लिए 11 अक्टूबर 2001 को रक्षा अधि ग्रहण परिषद की स्थापना की गई।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) रक्षा मंत्रालय के तहत् एक व्यापक संरचना, रक्षा खरीद योजना प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिए गठित की गई थी।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद का उद्देश्य मांग की गई क्षमताओं के संदर्भ में सशस्त्र बलों के अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद, और आवंटित बजटीय संसाधनों को बेहतर उपयोग करके, निर्धारित समय सीमा को सुनिश्चित करना है।

स्रोतः पीआईबी

नौसेना बेड़े में लैंडिंग क्राफ्ट यूटीलिटी एमके-IV के चौथे जहाज को शामिल किया गया

चर्चा में क्यों?

- एवीएसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ मैटेरियल वाइस एडमिरल जी.एस. पब्बी ने 25 मई 2018 को पोर्ट ब्लेयर में आईएन एलसीयू एल-54 जहाज को भारतीय नौसेना के बड़े में शामिल किया।
- भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएन एलसीयू एल 54 चौथा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) एमके-IV श्रेणी का जहाज है।

लैंडिंग क्राफ्ट यूटीलिटी एमके-IV

- जहाज का डिजाइन देश ही में तैयार किया गया है और इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने किया है।
- एल-54 देश की डिजाइन और जहाज निर्माण क्षमता का शानदार उदाहरण है।
- एलसीयू एमके-IV एक महत्वाकांक्षी जहाज है, जिसकी प्राथमिक भूमिका परिवहन और मुख्य युद्धक टैंक, सशस्त्र वाहनों, टुकड़ियों और उपकरणों की जहाज से तट तक तैनाती करना है।
- यह जहाज अंडमान और निकोबार कमान में हैं और इन्हें समुद्री तट के अभियानों, तलाशी और बचाव, आपदा राहत अभियानों, आपूर्ति और लदान तथा दूरदराज के द्वीपों से बाहर निकालने जैसे कई अभियानों में तैनात किया जा सकता है।
- लेफ्टिनेंट कमांडर मुनीश सेठी की कमान में इस जहाज में पांच अधिकारी, 41 नौसैनिक हैं और इसकी क्षमता 160 टुकड़ियों को ले जाने की है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

लाभ

- इस परियोजना के पांच अन्य जहाज निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं और डेढ़ साल के बाद इन्हें भारतीय नौ सेना में शामिल किया जाना है।
- इन जहाजों के नौ सेना में शामिल होने से राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

स्रोतः द हिंदू

रूस ने विश्व का पहला पानी पर तैरता परमाणु संयत्र लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- रूस ने 19 मई 2018 को विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया। अब तक किसी भी देश के पास इस प्रकार की तकनीक नहीं थी।

मुख्य तथ्य

- रूस ने इसे मुरमंस्क शहर के एक बंदरगाह से समुद्र में उतारा इसका नाम एकेडेमिक लोमोनोसोव (akademik lomonosov) है।
- यह रूसी जहाज एक परमाणु रिएक्टर है। जो अगले एक साल तक समुद्र में सफर पर रहेगा।
- अपने सफर के दौरान सबसे पहले यह पूर्वी रूस के शहर पेवेक जाएगा। इसको पूर्वी साइबेरिया ले जाने से पहले बंदरगाह पर संयंत्र में परमाणु ईंधन भरा जाएगा।

उद्देश्य

- एकेडेमिक लोमोनोसोव का उद्देश्य पूर्वी और उत्तरी साइबेरिया के दूरदराज के इलाकों में बिजली आपूर्ति करना और ऑयल रिफाइनिंग करना है।
- इसका निर्माण सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्तम ने सेंट्स पीटरसबर्ग में किया है यह परमाणु संयंत्र दो लाख की आबादी की बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- इसका निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन वित्तीय कमी से यह परियोजना लंबे समय तक लंबित रही।

एकेडेमिक लोमोनोसोव (Akademikl Lomonosov) की विशेषताएं

- इसका नाम रूस के अकदमीशियन मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है।
- रूस के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की लंबाई 144 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और वजन 21,000 टन है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इसमें 35 मेगावाट के दो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो रिएक्टर बर्फ के पहाड़ों को काटने वाले आइसबेकर शिप के रिएक्टर की तरह हैं।
- संयंत्र अपनी क्षमता से दो लाख की आबादी वाले शहर के लिए बिजली पैदा कर सकता है।
- इस तैरते हुए संयंत्र से दूरदराज के इलाकों में गैस और तेल उत्खनन प्लेटफॉर्मों को बिजली मिल सकेगी।
- रूस का दावा है कि इससे प्रतिवर्ष होने वाले 50 हजार टन कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है।
- इस रिएक्टर में काम करने के लिए 69 सदस्य हैं जो इसे चलाते हैं, इस परमाणु संयंत्र की आयु लगभग 40 वर्ष बताई गई है।
- इसके अतिरिक्त यह प्रतिदिन 2.4 लाख क्यूबिक मीटर पेयजल भी उत्पन्न करेगा।
- यह परियोजना रूस की सबसे महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इससे वह आर्कटिक क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध में मौजूद गैस व तेल के भंडार का संरक्षण कर सकेगा। इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि रूस के उत्तर से होकर गुजरने वाली समुद्री रास्ते पर रूस का सुरक्षा कवच पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हो सकेगां हालांकि कई पर्यावरण कार्यकर्ता इसे न्यूक्लियर टाइटैनिक बता चुके हैं जबकि ग्रीनपीस ने एकेडेमिक लोमोनोसोव को तैरता हुआ चेर्नोबिल बताया है।

स्रोतः द हिंदू

निपाह वायरस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में करेल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निपाह वायरस (NIV) के फैलने की पृष्टि की है।
- डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के रक्त तथा शारीरिक तरल द्वारा किये गये परीक्षण से इस वायरस की पुष्टि हुई है, निपाह वायरस को केरल के कोझिकोड़ जिले में दर्ज किया गया जहां दोनों पीड़ितों की मृत्यु हो गई।

निपाह वायरस (NIV) क्या है?

- यह एक ऐसा इंफेक्शन है जो फल खाने वाले चमगादड़ों द्वारा मनुष्यों को अपना शिकार बनाता है।
- यह इंफेक्शन सबसे पहले सुअरों में देखा गया लेकिन बाद में यह वायरस इंसानों तक भी पहुंच गया।
- वर्ष 2004 में बांग्लादेश में इंसानों पर निपाह वायरस ने हमला करना शुरू किया था।
- निपाह वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर फैलता है। इसमें अधिकतर खजूर एवं ताड़ी शामिल है।

निपाह वायरस कैसे फैलता है?

- विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस चमगादड़ से फैलता है। इन्हें फ्रूट बैट भी कहते हैं।
- जब यह चमगादड़ किसी फल को खा लेते हैं और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खाता है तो संक्रमित हो जाता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- निपाह वायरस इंसानों के अलावा जानवरों को भी प्रभावित करता है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयान नहीं हो पाई है।
- इससे संक्रमित व्यक्ति का डेथ रेट 74.5 प्रतिशत होता है।
- पहली बार इस वायरस पता डॉ. कॉबिंग चुआ ने 1998 में लगाया था। उस दौरान डॉ. बिंग मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से स्नातक कर रहे थे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वर्ष 1998 में मलेशिया में पहली बार निपाह वायरस का पता लगाया गया था। मलेशिया के सुंगई निपाह गांव के लोग सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित हुए थे। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। उस दौरान ऐसे किसान इससे संक्रमित हुए थे जो सुअर पालन करते थे।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट

- निपाह वायरस जानवरों और इंसानों में पाया जाने वाला एक नया तथा गंभीर इंफेक्शन है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार निपाह वायरस का जन्म टेरोपस जीनस नामक एक खास नस्ल के चमगादड से हुआ है। पहले इसके लक्षण सूअरों में देखने को मिले थे, वर्ष 2004 में इंसानों में भी इसके लक्षण पाए गए।

निपाह वायरस के लक्षण

- मनुष्यों में निपाह संक्रमण एन्सेफलाइटिक से जुड़ा हुआ है। इसमें मस्तिष्क की सूजन बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, विचलन, मानसिक भ्रम, कोमा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, इनसे रोगी की मौत भी होने का खतरा बना रहता है। निपाह वायरस का रोगी 24–48 घंटों के भीतर कोमा में जा सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है।

स्रोत : द हिंदू

नीति आयोग और एबीबी ने आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत् 23 मई 2018 को रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में विकास हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत में रोबोटिक्स को बढ़ावा देने तथा आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के लिए देश में अधिक स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया।

समझौते के मुख्य बिंदु

- नीति आयोग एबीबी के साथ मिलकर इकोनामी के मुख्य सेक्टर जैसे बिजली और पानी का सेक्टर, इंडस्ट्रीज जैसे फूड, हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर और रेल मेट्रो सेक्टर के डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर काम करेंगी।
- इस समझौते के तहत् इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी काम होगा। नीति आयोग और एबीबी सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- इस दौरान फीडबैक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी पर मंथन किया जायेगा।
- इस समझौते के तहत् एबीबी का विश्वस्तरीय सेंटर भी डिजिटलाइजेशन की समझ में मददगार साबित होगा।
- नीति आयोग पॉलिसीमेकर्स और सरकारी संस्थाओं को वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करेगा जो एबीबी की ओर से आयोजित किया जाएगा।
- इन कार्यक्रमों में एक्सपर्ट शामिल होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की क्षमताओं पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इससे उत्पादन क्षमता में क्रांति लाई जा सकती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence)

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- (i) इंसान की तरह सोचना (ii) इंसान की तरह व्यवहार करना, (iii) तर्क एवं विचारों युक्त तथ्यों को समझना एवं (iv) तर्क एवं विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर रोबोटिक कार्य, शंतराज खेलने वाला कंप्यूटर, मशीनी आधारित गणनाएं एवं विश्लेषण आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं-

एबीबी

- एबीबी का पूरा नाम एएसईए ब्राउन बॉवेरी है। यह मुख्यत: ऊर्जा और स्वचालन के क्षेत्रों में काम करने वाला एक स्विस-स्वीडिश बहुराष्ट्रीय निगम है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विटजरलैंड में है। एबीबी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कपनियों तथा सबसे बड़ी सामूहिक कंपनियों में से एक है। एबीबी विश्व के लगभग 100 देशों में कार्यरत है।

स्रोत : पीआईबी

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 21 मई 2018 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। यह भारत रूस के साझा उपक्रम से तैयार किया गया है।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के अनुसार ओडिशा तट पर चांदीपुर में एकीकृत टेस्ट रेंज (आईटीआर) में मौजूद मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया गया था।

उद्देश्य

- परीक्षण का उद्देश्य इस मिसाइल की कार्यअवधि को 10 से 15 वर्षों तक बढ़ाना था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पहली भारतीय मिसाइल :

- ब्रह्मोस पहली भारतीय मिसाइल है जिसकी कार्यअवधि 10 से 15 साल तक बढ़ा दी गई है।
- ब्रह्मोस मिसाइल के जीवन को बढ़ाने की प्रौद्योगिकियां पहली बार भारत में विकसित की गई हैं।

भारतीय सेना में शामिल :

- भारतीय सेना ने अपने शस्त्रागर में ब्रह्मोस की तीन रेजिमेंटों को पहले ही शामिल कर लिया है। सभी मिसाइल के ब्लॉक-III संस्करण से लैस हैं।

मिसाइल में विशेषताएं :

- मिसाइल में खासियत है कि इस चलाने देने के बाद यह खुद-ब-खुद ऊपर और नीचे की उड़ान भरकर जमीन के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस तरह यह दुश्मन के वायु रक्षा प्रणालियों से बच निकलती है।
- भारतीय सेना में ब्रह्मोस के जमीनी हमले करने वाला संस्करण 2007 से इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इसकी सटीकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जमीनी लक्ष्य को 10 मीटर की ऊंचाई तक से भेद सकती है।

ब्रह्मोस मिसाइल:

- ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर से ही किया गया था।
- ब्रह्मोस एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है।
- यह घनी शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है।
- ब्रह्मोस मिसाइल दो चरणीय वाहन है। इसमें ठोस प्रोपेलेंट बुस्टर तथा एक तरल प्रोपेलेंट रैम जैम सिस्टम लगा हुआ है।
- यह मिसाइल 8.4 मीटर लम्बी तथा 0.6 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 3 हजार किलोग्राम है।
- यह मिसाइल 300 किग्रा. वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 350 किमी. तक मार करने की क्षमता रखती है।
- यह सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से भी 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखती है।
- इस मिसाइल को पानी के जहाज, हवाई जहाज, जमीन एवं मोबाइल लंचर से छोड़ा जा सकता है।
- इस मिसाइल को किसी भी दिशा में लक्ष्य की तरफ मनचाहे तरीके से छोड़ा जा सकता है।
- इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है।
- यह मिसाइल तकनीक थलसेना, जलसेना और वायुसेना तीनों के काम आ सकती है।

स्रोत : द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

बौद्धिक संपदा के मस्कट 'आईपी नानी' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय वणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 16 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतीक चिन्ह (मस्कट) आईपी नानी का शुभारंभ किया।

  समारोह के दौरान सुरेश प्रभु ने एंटी पायरेसी वीडियो भी लांच किया। इसे विडियो में अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई है।

आईपी नानी

- मस्कट आईपी नानी तकनीक को समझने और उपयोग करने वाली एक नानी है, जो अपने पोते 'छोटू' आदित्य की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद करती है।
- यह आईपी मस्कट सुरूचिपूर्ण ढंग से लोगों विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता फैलायेगा।
- यह चरित्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के अभियान के अनुरूप है जो महिलाओं की प्रतिभा सरलता जिज्ञासा और साहस को दुनिया में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण मानता है।
- यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक मजबूत आईपी प्रणाली नवोन्मेषी ओर रचनात्मक महिलाओं को समर्थन प्रदान करती है।

आईपी नानी: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति का एक हिस्सा

- सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आईपीआर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। केन्द्रीय कैबिनेट ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय आईपीआर नीति को मंजूदी दी थी।
- इस नीति के तहत् इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों को मानता है और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए यहां प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचा मौजूद है।
- ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही प्रयाप्त नहीं है बल्कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के चोरी किये जाने के संदर्भ में जागरूकता फैलानी चाहिए और इस प्रयास में समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- आईपी नानी पर आधारित वीडियो सीआईपीएएम के यूट्यूब चैनल (सीआईपीएएम इंडिया), ट्वीटर हैंडल और फेसबुक पेज पर उपलब्ध है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

राष्ट्रीय आईपीआर नीति के उद्देश्य :

- बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता: पहुंच और प्रोत्साहन–समाज के सभी वर्गो में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन–बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा।
- वैधानिक एवं विधायी ढांचा–मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
- प्रशासन एवं प्रबंधन–सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण–व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण
- प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरण–बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- मानव संसाधन विकास–मानव संसाधनों, का शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना।

स्रोत: पीआईबी

WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्ति हेतु रिप्लेस गाइड जारी की

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 15 मई 2018 को 'REPLACE' (रिप्लेस) गाइड जारी की इसका उद्देश्य वर्ष 2023 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांस फैट एसिड को समाप्त करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रांस फैट से होने वाले हृदय रोगों से प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 5,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।

रिप्लेस (REPLACE) छह सूत्रीय कार्यक्रम

- रिप्लेस के तहत् छह सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा।
- **रिव्यु (Review) :** औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों की समीक्षा करना।
- **प्रमोट (Promote) :** ट्रांस फैट की अपेक्षा स्वस्थ फैट और तेलों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।
- **लेजिस्लेट (Legislate) :** औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए विधि या विनियामक कार्यों को लागू करना।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- **एसेस (Assess) :** खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट सामग्री का आकलन और निगरानी करना।
- **क्रिएट (Create) :** ट्रांस फैट से स्वास्थ्य के होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **एनफोर्स (Enforce) :** नीतियों और विनियमों के अनुपालन को लागू कराना।

ट्रांस फैट क्या है?

- ट्रांस फैट दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक ट्रांस फैट और दूसरा कृत्रिम ट्रांस फैट नेचुरल ट्रांस फैट जानवरों और उनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थों में संतुलित मात्रा में मौजूद होता है। इसका हमारी सेहत पर ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। वही कृत्रिम ट्रांस फैट इंडस्ट्रीज में प्रॉसेस किए गए वेजिटेबल और अन्य प्रकार के तेलों में पाया जाता है। ये सस्ते होते हैं और सबसे प्रमुख खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं।
- ट्रांस फैट के चलते हृदय संबंधित बीमारी, हाइपरटेंशन, मोटामा और डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती है। ट्रांस फैट केक, कुकीज, बिस्किट, क्रीम कैंडीज, फास्ट फूड, डोनट्स और क्रम बेस्ड अन्य फूड आइटम में अधिक होता है।

स्रोतः द हिंदू

भारतीय सेना ने 15,000 करोड़ रुपये की हथियार उत्पादन परियोजना को मंजूदी दी

चर्चा में क्यों?

- भारतीय थल सेना द्वारा हथियारों और टैंकों के गोला-बारूद का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। अब गोला-बारूद का उत्पादन भारत में ही होगा तथा सेना की आवश्यकता अनुसार इसे उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- इस परियोजना का उद्देश्य गोला-बारूद के आयात में होने वाली लंबी देरी और इसका भंडार घटने की समस्या का हल करना है। पिछले कुछ वर्षों से जरूरी गोला-बारूद का भंडार तेजी से घट रहा था जिसके चलते सेना ने कई बार चिंता भी जाहिर की थी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

- इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 11 निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन की निगरानी थल सेना और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी करेंगे।
- इस परियोजना का त्वरित लक्ष्य गोला-बारूद का स्वदेशीकरण है। इसके तहत् सभी बड़े हथियारों के लिए एक इंवेंट्री बनाई जाएगी, ताकि सुरक्षा बल 30 दिनों का युद्ध लड़ सके जबकि इसका दीर्घकालीन उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाना है।
- परियोजना की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपये है तथा गोला-बारूद की मात्रा के संदर्भ में अगले 10 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- आरंभिक चरण में विभिन्न रॉकेटों, हवाई रक्षा प्रणाली, तोपों, बख्तरबंद टैंकों, ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य के लिए गोला-बारूद का उत्पादन समयसीमा के अंदर किया जाएगा।
- उत्पादन के लक्ष्यों के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रथम चरण के नतीजे के बाद संशोधित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने जुलाई 2017 में संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 152 प्रकार के गोला बारूद में सिर्फ 61 प्रकार का भंडार ही उपलब्ध है और युद्ध की स्थिति में यह सिर्फ 10 दिन चलेगा। जबकि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक गोला-बारूद का भंडार एक महीने लंबे युद्ध के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

स्रोतः द हिंदू

भारतीय सेना का युद्धाभ्यास 'विजय प्रहार' सफलतापूर्वक संपन्न

चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर की महाजन फील्ड फायरिंग में दक्षिण पश्चिमी कमान का एक बड़ा युद्धाभ्यास ''विजय प्रहार'' 40 दिन चलने के बाद 09 मई, 2018 को संपन्न हुआ।

मुख्य तथ्य

- इस युद्धाभ्यास भारतीय सेना को परमाणु हमले से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस युद्धाभ्यास में 20,000 सैनिकों ने पूरे हथियारों एवं साजो-सामान के साथ हिस्सा लिया था।
- युद्धाभ्यास के अंतिम दिन रेत के धारों के बीच सैनिकों ने टैंक से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने दुश्मन के क्षेत्र में असमान से जमीन पर उतर कर धावा बोलने सहित अन्य कौशल का प्रदर्शन किया।
- इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के साथ भी बेहतर किस्म का समन्वय स्थापित हुआ। भविष्य में युद्ध होने के हालात में रासायनिक और परमाणु हथियारों से निपटने के लिए सेना के अधिकारियों एवं जवानों ने रेगिस्तान के रेतीले धारों में 45 से 46 डिग्री तापमान के दौरान न्यूक्लियर पोटेक्शन सूट पहनकर युद्धाभ्यास किया।

पृष्ठभूमि:

- युद्धाभ्यास ''विजय प्रहार'' एक आक्रामक रणनीति के तहत् वायु एवं पृथ्वी में समन्वित युद्ध के तौर पर पूरी खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए शुरू हुआ था। अभ्यास में एयर कैवेलरी रणनीति का पूरी तरह से प्रयोग किया गया था। अब सभी सैनिक किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार हैं। भीषण गर्मी एवं आंधी के वातावरण में जवानों द्वारा पूरी वीरता एवं निष्ठा से किए गए इस युद्ध अभ्यास की काफी सराहना की गई।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

सेना पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ भारत

चर्चा में क्यों?

सेना पर खर्च के मामले में भारत अब दुनियाभर के देशों में पांचवे पायदान पर आ गया है। वर्ष 2017 में भारत के सैन्य खर्च में साढ़े पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है,

मुख्य तथ्य

- इसी के साथ भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। यह जानकारी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की सलाना रिपोर्ट में सामने आई है।
- सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 60 फीसदी अकेले भारत और चीन का है।

- सिपरी के मुताबिक वर्ष 2017 में वैश्विक सैन्य खर्च में वर्ष 2016 के मुकाबले 1.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।
- सैन्य खर्च का आंकड़ा वर्ष 2017 में 115.92 लाख करोड़ रुपए कर रहा, जो वैश्विक जीडीपी का 2.2 फीसदी है। कुल सैन्य खर्च वर्ष 2016 में 112 लाख करोड़ रूपए था।

चीन के तुलना में भारत का सैन्य खर्च:

- चीन के मुकाबले भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में भारत ने सैन्य खर्च साढ़े पांच फीसदी बढ़ाया है।
- इस खर्च में 14 लाख मौजूदा और करीब 20 लाख रिटायर्ड सैन्यकर्मियों की जरूरतें भी शामिल हैं, भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2017 में 42.6 लाख करोड़ रुपए रहा।
- हालांकि चीन अभी भी सैन्य खर्च के मामले में भारत से 36 गुना आगे है चीन ने अपना सैन्य खर्च करीब 80 जहार करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए 15.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया हैं।

सैन्य खर्च में शीर्ष 5 देश:

स्थान	देश	खर्च (लाख करोड़ रुपये)
1.	अमेरिका	40.68
2.	चीन	15.19
3.	सऊदी अरब	4.60
4.	रूस	4.40
5.	भारत	4.26

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- वहीं दूसरी ओर रूस का रक्षा खर्च 1998 के बाद पहली बार घटा है। रूस का रक्षा खर्च वर्ष 2017 में 66.3 अरब डॉलर रहा है जो वर्ष 2016 की तुलना में 20 प्रतिशत कम है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस से बढ़ते खतरे की आशंका से मध्य और पश्चिमी यूरोप वे सैन्य खर्च में वर्ष 2017 में क्रमशः 12 और 1.7 फीसद की वृद्धि हुई।
- रिपोर्ट के मुताबिक, नाटो के सभी 29 सदस्य देशों का कुल रक्षा खर्च 900 अरब डॉलर रहा। यह वैश्विक रक्षा खर्च का 52 फीसदी है।
- सैन्य खर्च में हालिया कटौती भी आर्थिक संकटों के कारण की गई है। जिनमें वर्ष 2014 में तेल की कीमतों में गिरावट, दो साल मंदी शामिल हैं।

स्रोत : द हिंदू

ELITE IAS

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई 2018 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 का विषय है सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडायवर्सिटी (Celebrating 25 Years of Action for Biodiveristy)
- प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव-विविधता का महत्व देखते हुए ही जैव-विविधता दिवस को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है, जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान कर सके।
- इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र-भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव-विविधता के महत्व एवं उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है।
- जैव विविधता सभी जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्ता एवं असमानता को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी विशेष रूप से कहा कि 2030 के सतत विकास एजेंडा के लिए जैव विविधता आवश्यक है।
- वैश्विक नेताओं ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक जीवित नक्षत्र सुनिश्चित करते हुए वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए 'सतत विकास' की एक व्यापक रणनीति पर सहमति व्यक्त की थी। 193 सरकारों ने इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर 2000 को 55/201 प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाये जाने का संकल्प लिया।
- इस दिवस का उद्देश्य 22 मई 1992 को पारित किये गये नौरोबी एक्ट का पालन करना तथा इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है।
- अधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता था।

जैव विविधता का तात्पर्य :

- जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु और पेड़-पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। इसकी कमी से बाढ़, सूखा और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की अहम भूमिका होती है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

उत्तर पूर्व में 'गज यात्रा' आरंभ की गई

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 मई 2018 को गारो पर्वतों में स्थित तूरा नामक गांव से 'गज यात्रा' का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की।

गज यात्रा

- गज यात्रा का उद्देश्य भारत में मौजूद हाथियों की आवाजाही के लिए उन्हें सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना है। गज यात्रा के तहत भारत में 100 'एलीफेंट कॉरिडोर' बनाए जायेंगे, इसमें से चार मेघालय में स्थित हैं, जिसमें से एक सिजू-रेवाक कॉरिडोर है जहां रोजाना लगभग 1,000 हाथी बालपक्रम एवं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यानों के बीच आते-जाते हैं।
- उत्तर-पूर्व भारत में यह अभियान विशेष रूप से गारो पहाड़ियों में लॉन्च किया गया। इस स्थान पर लोगों ने सामुदायिक वनों का निर्माण किया है ताकि इस क्षेत्र में मौजूद हाथियों का संरक्षित किया जा सके तथा लोगों के साथ उनका बेहतर ताल-मेल स्थापित हो सके।
- हाथियों की बहुलता वाले 12 राज्यों में वहां की स्थानीय कला और दस्तकारी में हाथी औन अन्य वन्य जानवरों के प्रसंग को शामिल किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया 'गजु शुभंकर हाथी इस अभियान में प्रमुखता में शामिल किया जा रहा है। यह अभियान वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के सहयोग से चलाया जाता है।

उद्देश्य

- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हाथियों का संरक्षण है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन हाथी, 'कमजोर हाथी' एवं एशियान हाथी 'लुप्त प्राय श्रेणी में दिखाए गए है।
- हाथियों की जनसंख्या के बारे में प्राप्त आकलन के अनुसार विश्व भर में 4,00,000 अफ्रीकन हाथी और 40,000 एशियान हाथी हैं।
- भारत सरकार इस अभियान को हाथियों के प्रति जागरूकता और इनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए इसे चला रही है।

राईट ऑफ पैसेज क्या है?

- हाथियों के लिए सामुदायिक क्षेत्रों में सुरक्षित आवाजाही के रास्ते तैयार करना।
- इस अभियान के तहत् स्थानीय लोगों की सहायता ली जा रही हैं उन्हें वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा प्रशिक्षित करके हाथियों के संरक्षण में भूमिका तय की जाती है।
- एक राष्ट्रीय उद्यान, वन अथवा वनीय क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के लिए मार्ग का निर्माण किया जाता है। जिसमें स्थानीय लोगों को अपने आसपास के परिवेश में बदलाव करने के लिए कहा जाता है।
- मसलन, उन्हें अधिक वृक्ष लगाने, हाथियों की आवाजाही के दौरान विघ्न न डालने एवं वनों को संरक्षित करने के लिए कहा जाता है।

स्रोतः पीआईबी

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन हैम्बर्ग में आयोजित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

- वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन का प्रथम संस्करण 25-28 सितंबर 2018 को जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया जायेगा।

पहले वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन की विशेषताएं

- पहला पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन-2018 व्यापार, नेटवर्किंग तथा सूचना के लिहाज से पवन ऊर्जा इंडस्ट्री के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।
- शिखर सम्मेलन में दो सम्मेलन 'विंडइनेर्जी हैम्बर्ग' और 'विंडयुरोप' शामिल हैं।
- विंड यूरोप, विंड एनर्जी की सहायता से हैम्बर्ग में वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
- पवन ऊर्जा से सम्बंधित इस सम्मेलन में 1400 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कार्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य नेटवर्क, व्यापार एवं दुनियाभर में लोगों के बीच पवन ऊर्जा का प्रसार करना होगा।
- विंडयूरोप के 250 विशेषज्ञों द्वारा 50 से अधिक सेमिनारों में भाग लिया जायेगा तथा 2018 के पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन को सफल बनाया जायेगा।
- इस कार्यक्रम में भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन एवं डेनमार्क सहित 100 से अधिक देश भाग लेंगे।
- इस शिखर सम्मेलन से विश्व भर से आये विशेषज्ञों को इको-फ्रेंडली तकनीक के लिए एक प्लेटफार्म प्राप्त होगा।
- इस आयोजन के दौरान होने वाली बैठकों के माध्यम से नये बाजारों की खोज, उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करना आदि शामिल है।

वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन के तीन मुख्य विषय

- पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित तीन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
  - डायनामिक बाजार
  - कम लागत, और
  - स्मार्ट ऊर्जा

शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका

- इस सम्मेलन में भारत की ओर से विभिन्न कम्पनियां भाग ले रही हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के हिसाब से भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है।
- भारत में चीन के बाद 33 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। भारत से पहले चीन, अमेरिका एवं जर्मनी का स्थान आता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- भारतीय सरकार ने वर्ष 2022 तक 60 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्लोबल वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल, स्टीव सॉयर के अनुसार भारत सौर ऊर्जा का बढ़ता हुआ तथा बड़ा बाजार है।
- वर्तमान समय में इस क्षेत्र की बहुत सी कम्पनियां भारत की ओर देख रही हैं।

स्रोतः द हिंदू

भारत में सिंधु डॉल्फिन की पहली संगठित जनगणना आरंभ की गई

चर्चा में क्यों?

- पंजाब सरकार ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन (Indus Dolphin) की जनगणना आंरभ की यह विश्व की विलुप्त प्राय स्तनधारी प्रजाति है।
- इसका उद्देश्य इस प्रजाति का संरक्षण करना है। सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फि केवल भारत ओर पाकिस्तान के मध्य 185 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। यह डॉल्फिन तलवाडा तथा हरिके पत्तन के बीच भारत की व्यास नदी में पाई जाती हैं।

उद्देश्य

- इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति की डॉल्फिन की सटीक जनसंख्या का पता लगाना है। इसके उपरांत ही इनके संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

महत्व

- यह भारत की पहली संगठित डॉल्फिन जनगणना है जिसे पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा। इससे पहले बहुत कम डॉल्फिन चिन्हित की गई थी।
- पंजाब सरकार के वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया इस कार्य को मिलकर पूरा करेंगे। इसके अंतर्गत दो टीमें बनाकर डॉल्फिन की जनगणना की जाएगी।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

- सिंधु डॉल्फिन (Indus Dolphin) की प्रजाति मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। इस क्षेत्र में डॉल्फिन की जनसंख्या अनुमानतः 1800 से अधिक है।
- भारत में इस प्रजाति की डॉल्फिन की बेहद कम संख्या मौजूद है जो कि केवल ब्यास नदी में पाई जाती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, सदियों पहले इस प्रजाति की डॉल्फिन सतलुज नदी में पाई जाती थी। सतलुज में हुए प्रदूषण एवं शहरीकरण के कारण इस नदी की सभी डॉल्फिन विलुप्त हो गई।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार वर्ष 1944 से अब तक इस क्षेत्र में पाइ जानी वाली डॉल्फिन की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की कमी आई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के रिवर वेटलैंड एंड वॉटर पालिसी के निदेशक सुरेश बाबू द्वारा जारी बयान में कहा गया कि डॉल्फिन की मौजूदगी नदी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है। यदि नदी साफ-सुथरी है तो वहां डॉल्फिन रह पाएंगी अन्यथा सतलुज से विलुप्त हुई डॉल्फिन का उदाहरण सबके सामने है।

स्रोतः द हिंदू

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

आंतरिक सुरक्षा

स्थानीय आदिवासियों से निर्मित बस्तरिया बटालियन सी.आर.पी.एफ में शामिल

चर्चा में क्यों?

- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के रंगरूटों की बहुप्रतीक्षित बस्तरिया बटालियन 21 मई 2018 से केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सेवा में आ गई है।
- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अंबिकापुर जिले में इसके पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।
- बस्तरिया बटालियन की विशेषता यह है कि इसमें इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों को शामिल किया गया है।
- यह सभी जवान यहां की स्थानीय भाषा और इलाके को भली-भांति समझते हैं, जबकि सीआरपीएफ ने ही इन जवानों को ट्रेनिंग दी है।

बस्तरिया बटालियन नाम क्यों?

- सीआरपीएफ की 24 वी नंबर की इस नई बटालियन का नाम बस्तरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इस दल में सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र की सीमाई इलाकों के आदिवासियों को शामिल किया गया है।
- बस्तरिया शब्द को बस्तर से लिया गया है, जो कि यहां का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।
- बस्तरिया बटालियन के जवानों को 44 हफ्ते तक जंगल में युद्ध, हथियान, नक्शा पढ़ने, कानून और बिना हथियार के लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई है।

बस्तरिया बटालियन में महिलाएं

- सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन की पहली खेप में 189 महिला जवान शामिल हैं जबकि इस बटालियन में कुल जवानों की संख्या 534 है।
- इस बटालियन में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान दिया गया है। महिलाओं को इसमें शामिल करने का एक उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय महिलाओं के सेना में आने से आदिवासियों के बीच एक बेहतर संदेश जाएगा और नक्सलवाद की ओर से उनका रूझान कम होगा।
- आदिवासियों को सरकार के साथ लाने में भी ये लड़ाके काम करेंगे, जिससे बस्तर क्षेत्र में शांति आएगी।

बस्तरिया बटालियन से लाभ

- सीआरपीएफ की इस विशेष बटालियन के जवान सुरक्षाबलों और स्थानीय लोगों के बीच कड़ी का काम कर सकेंगे।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- सेना इस क्षेत्र में आसानी से गांव के लोगों से घुल-मिल सकते हैं तथा उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- जवानों के लिए भाषा की दिक्कत खत्म होगी। बस्तरिया के जवान स्थानीय भाषा के ज्ञान के कारण बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे।
- बस्तरिया के जवानों को स्थानीय इलाकों की पूरी जानकारी होने के कारण सेना को अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- बस्तरिया जवानों को स्थानीय परंपराओं की समझ होने के कारण पैरामिलिट्री के जवानों और स्थानीय आदिवासियों के बीच की कई तरह की गलत फहमियां दूर होंगी।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

अन्य खबरें

कैलाश सत्यार्थी और किरण कुमार 'संतोकबा ह्यूमैनेटेरियन अवार्ड' से सम्मानित

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 मई 2018 को नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और इसरो के पूर्व अध्यक्ष ए एस किरण कुमार को 'संतकोबा ह्यूमैनेटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत दोनों को एक-एक करोड़ रुपए की राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई।
- यह समारोह सूरत के संजीव कुमार आडीटोरियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली और मुख्यमंत्री विजय और प्रौद्ययोगिकी में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए पुरस्कार राशि समर्पित करने की घोषणा की।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2018 को विश्व भर में मनाया गया। तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार स्वास्थ्य, कानूनी और आर्थिक, शासन और भ्रष्टाचार सहित प्रमुख वैश्विक चिंता का विषय है।
- विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2018 का थीम: तंबाकू और हृदय रोग (Tobacco and heart disease)

उद्देश्य

- दूसरों पर इसकी जटिलताओं के साथ ही तंबाकू इस्तेमाल के नुकसानदायक प्रभाव के संदेश को फैलाने के लिये वैश्विक तौर पर लोगों का ध्यान खींचना इस दिवस का लक्ष्य है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी देशों से तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की अपील की है ताकि नये लोगों को तंबाकू सेवन का आदी होने से बचाया जा सके।
- यह दिन सभी रूपों में तंबाकू की और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करता है और तंबाकू खपत से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाये जाने की घोषणा की थी।

पंकज सरन भारत के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

- भारत के वरिष्ठ राजनयिक पंकज सरन को उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा 29 मई 2018 को यह जानकारी सार्वजनिक की गई। पंकज सरन फिलहाल रूस में भारत के राजदूत हैं।
- कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डिप्टी एनएसए के रूप में सरन की दो वर्ष के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

पंकज सरन के बारे में जानकारी

- वर्ष 1982 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी को नवंबर 2015 में रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था।
- वह भारत और विदेश में कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। वे दो बार प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवाएं दे चुके हैं
- पहले 1995 से 1997 तक उपसचिव, निदेशक के रूप में और फिर 2007 से 2012 तक संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे।
- खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। रॉ के पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना को भी इस साल जनवरी में डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के मुख्य कार्यकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक सलाहकार होते है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण	पदभार मुक्ति	प्रधानमंत्री
1.	ब्रजेश मिश्र	नवंबर, 1998	मई 2004	अटल बिहारी वाजपेयी
2.	जे.एन. दीक्षित	मई, 2004	जनवरी 2005	डॉ. मनमोहन सिहं
3.	एम. के. नारायणन	जनवरी, 2005	जनवरी 2010	डॉ. मनमोहन सिंह
4.	शिव शंकर मेनन	जनवरी, 2010	मई 2014	डॉ. मनमोहन सिंह
5.	अजीत डोभाल	मई, 2014	अब तक	नरेंद्र मोदी

चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार जीता IPL का खिताब

- चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने शेन वॉटसन की शानदर शतकीय पारी की बदौलत आईपीएल 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सीएसके ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही।
- मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 27 मई 2018 को खेले गए आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट खोकर 9 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मैन ऑफ द मैच:

- शेन वॉटसन को शानदार पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच से नावाजा गया उन्होंने 57 गेदों पर 11 चौकों और 8 छक्को की मदद से 117 रन की नाबाद पारी खेली।

सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पहली टीम:

- चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के एक सीजन में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। मौजूदा सीजन में चेन्नई ने फाइनल सहित सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रिकॉर्ड 4 मैचों में जीत दर्ज की है जो आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है।

चेन्नई तीसरी बार चैपियन:

- चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी बार आईपीएल का विजेता बना। दो साल बाद लीग में वापसी करने वाली चेन्नई की यह तीसरी खिताबी जीत है। इससे पहले वो वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में खिताब अपने नाम कर चुकी है। इसी के साथ वह सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस के बराबर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों के नाम सबसे ज्यादा तीन-तीन खिताब हैं। यह चेन्नई का सातवां आईपीएल फाइनल था।

आईपीएल चैंपियन कौन कितनी बार बना?

	टीम	वर्ष	कप्तान
1.	चेन्नई सुपर किंग्स	3 बार (वर्ष 2010, वर्ष 2011 और वर्ष 2018)	महेंद्र सिंह धोनी
2.	मुंबई इंडियंस	3 बार (वर्ष 2013, वर्ष 2015 और वर्ष 2017)	रोहित शर्मा
3.	कोलकाता नाइट राइडर्स	2 बार (वर्ष 2012 और वर्ष 2014)	गौतम गंभीर
4.	सनराइजर्स हैदराबाद	1 बार (वर्ष 2016)	डेविड वॉर्नर
5.	डेक्कन चार्जर्स	1 बार (वर्ष 2009)	एडम गिलक्रिस्ट
6.	राजस्थान रॉयल्स	1 बार (वर्ष 2008)	शेन वॉर्न

चेन्नई सुपर किंग्स पर दो साल का प्रतिबंध:

- चेन्नई सुपर किंग्स को वर्ष 2016 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आने के कारण टीम पर 2 साल का प्रतिबंधित लगा दिया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स टीम को वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के आईपीएल में खेलने पर प्रतिबंधित किया गया था।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)

- इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित ट्वेन्टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता है। लीग वर्ष 2007 में भारत (बीसीसीआई) के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। आईपीएल अप्रैल और हर साल के मई के ऊपर निर्धारित है। वर्ष 2016 में आईपीएल का टाइटल प्रायोजक विवो इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार लीग को आधिकारिक तौर पर विवो इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में जाना जाता है।

  आईपीएल की नीलामी हर साल होती है। आईपीएल के नियम के अनुसार कोई भी टीम ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 28 खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर सकती है। जिसमें से 8 खिलाड़ी विदेशी कोई भी टीम अपनी टीम में शामिल कर सकती है।

धोनी ने आईपीएल में रचा इतिहास

- मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में 27 मई, 2018 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 11 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक 33 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए।
- धोनी से पहले यह रिकॉर्ड 32 स्टंपिंग के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा के नाम था। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन आईपीएल में धोनी की स्टंपिंग का 33वां शिकार बने।
- धोनी आइपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा आइपीएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी है। धोनी ने अभी तक 8 खिताबी मुकाबलों में शिरकत की है।
- धोनी ने सात फाइनल तो सीएसके की तरफ से ही खेले हैं जबकि एक फाइनल उन्होंने पुणे सुपर जाएंट के लिए 2017 में खेला था।
- मुंबई के खिलाफ मैदान पर उतरते ही महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के 150 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान बन गए।

पोलैंड की ओल्गा टोकर्कजुक ने मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त किया।

- पोलैंड की साहित्याकार ओल्गा टोकर्कजुक ने 22 मई 2018 को प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार उनके फिक्शन उपन्यास ''फ्लाइट्स'' के लिए दिया गया।
- 'फ्लाइट्स' के साथ कुछ अन्य उपन्यास भी पुरस्कार की दौड़ में शामिल थे लेकिन ओल्गा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पुरस्कार हासिल किया। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए नामांकित उपन्यासों में इराकी लेखक अहमद सदावी की हॉरर कहानी 'फ्रैंकइंस्टीन इन बगदाद' तथा दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग के उपन्यास 'द वाइट बुक' शामिल थे। टोकर्कजुक का उपन्यास 17वीं शताब्दी के रचनात्मकता की कहानी के साथ आधुनिक-दिन की कथा यात्रा को जोड़ता है, जिसमें एक शरीररचना-वैज्ञानिक स्वंय अपनी विकलांग टांग को पृथक कर देता है तथा साथ ही संगीतकार फ्रेडरिक चोपिन की पेरिस से वॉरसॉ की यात्रा को प्रदर्शित करता है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

- लेखक लिसा एपिनेंसेनी के नेतृत्व में निर्णय पैनल ने ''फ्लाइट्स'' को एक मजेदार, चंचल उपन्यास कहा, जिसमें ''सतत द्वंद्व की समकालीन स्थिति'' मृत्यु की निश्चितता को पूरा करती है।

मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार

- यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिए मैन बुकर पुरस्कार के समकक्ष है और अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा में पुस्तकों के लिए खुला है।
- 50,000 पौंड (67,000 डॉलर) पुरस्कार लेखक और उसके अनुवादक जेनिफर क्रॉफ्ट के बीच समान रूप से विभाजित होंगे।
- मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाठकों को बेहतरीन किताबों को पुरस्कृत करता है।
- वर्ष 2016 से मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार को एक पुस्तक के लिए सालाना सम्मानित किया जाता है। इसका अनुवाद अंग्रजी में किया गया हो और उसे यूके में प्रकाशित किया गया हो।
- वर्ष 2018 में मैने बुकर पुरस्कारों ने अपने 50 वर्ष पूरे किये हैं। इस उपलक्ष्य में विश्व भर में साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

उच्चतम पछरने को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

- उच्चतम पछरने को 17 मई 2018 को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति राम नाथक कोविंद ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। उत्तम पछरने एक प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकर हैं।
- इससे पहले मार्च, 2018 में संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव (शैक्षिक) एम.एल. श्रीवास्तव को ललित कला अकादमी का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जिसके कारण नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित थी।

  उच्चतम पछरने कार्यभार संभाले जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए इस पद पर रहेंगे।

ललित कला अकादमी

- ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित द्वारा स्थापित की गई।
- यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था।
- ललित कला अकादमी के 30 परिपूरक स्वीकृत कला संगठन संपूर्ण देश में हैं जो कि अकादमी के क्रियाकलापों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 12 राज्य ललित कला अकादमी हैं जो केंद्रीय अकादमी की सहायक और सहकारी हैं।
- अकादमी के बजट में देशी और प्रांतीय अकादमी के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था है।
- राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी प्रति वर्ष समकालीन भारतीय कला की श्रेष्ठ प्रतिनिध्यात्मक कृतियों का चयन प्रस्तुत करती है।
- ललित कला ग्रंथमाला की समकालीन कला के लेखों में प्रख्यात अभ्यासरत कलाकारों की चर्चा होती है।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

भारतीय मूल के वैज्ञानिक ई.सी. जॉर्ज सुदर्शन का निधन

- भारतीय मूल के वरिष्ठ भौतिक वैज्ञानिक ई.सी. जॉर्ज सुदर्शन का 13 मई 2018 को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी भामथी सुदर्शन के अलावा दो बच्चे हैं।
- उन्हें नौ बार भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वे लगभग 40 सालों से अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे।

ई.सी.जॉर्ज सुदर्शन के बारे में

- ई. सी. जॉर्ज सुदर्शन का जन्म केरल के कोट्टायम जिले के पल्लम गांव में 1931 में हुआ था।
- उन्होंने कोट्टायम के सीएमएस कॉलेज से पढ़ाई की थी और मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से किया था।
- उन्होंने होमी जहांगीर भाभा के साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में थोड़े समय के लिए काम भी किया था।
- वर्ष 1958 में उन्होंने यूनिवर्सिटी और रोचेस्टर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
- इसके बाद उन्होंने नोबले पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जूलियन स्चेविंगर के निर्देशन में पोस्ट-डाक्टरेट की।
- वर्ष 2005 में उन्हें अन्य वैज्ञानिकों के साथ फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन उनके साथ मिलकर 'सुदर्शन-ग्लाबेर रिप्रजेंटेशन' बनाने वाले भौतिक विज्ञानी रॉय जे ग्लाबेर को उस साल के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अन्य वैज्ञानिकों के साथ दिया गया।
- उन्होंने क्वांटम ऑपटिक्स, क्वांटम जीनो इफेक्ट व क्वांटम कंप्यूटेशन से जुड़े कई सिद्धांत दिए और खोज की।

विश्व के सबसे ताकतवार लोगों की सूची

- अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2018 के सबसे ताकतवार लोगों की सूची जारी की गई इस सूची में नरेंद्र मोदी टॉप-10 शख्सियतों में शामिल हैं उन्हें नौवां स्थान मिला है।
- फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग पहले नंबर पर हैं जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दूसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष व्लादिमीर पुतिन इस सूची में पहले नंबर थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष भी नौवें स्थान पर ही मौजूद थे।

फोर्ब्स की सूची (टॉप-10 रैंकिंग)

रैंक	नाम
पहला	शी चिनफिंग (चीन के राष्ट्रपति)
दूसरा	व्लादिमीर पुतिन (रूस के राष्ट्रपति)
तीसरा	डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका के राष्ट्रपति)

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

चौथा	एंजेला मर्कल (जर्मनी की चांसलर)
पांचवां	जेफ बेजोस (ऐमजॉन के मालिक)
छठा	पोप फ्रांसिस (रोमन कैथलिक चर्च)
सातवां	बिल गेट्स (बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन)
आठवां	मोहम्मद बिन सलमान (सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस)
नौवां	नरेंद्र मोदी (भारत के प्रधानमंत्री)
दसवां	लैरी पेज (गूगल)

सूची से सम्बंधित अन्य जानकारी

- फोर्ब्स द्वारा इस सूची में कुल 75 शख्सियतों को शामिल किया गया है।
- फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों (12), अलीबाबा के प्रमुख जैक मा (21) भी इस सूची में शामिल हैं।
- फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग (13), ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा में (14), चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग (15), एप्पल के सीईओ टिम कुक (24) को भी सूची में रखा गया है।
- रिलांयस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (32) इस सूची में मोदी के अलावा स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के सत्य नडेला को 40वें पायदान पर रखा गया है।

राष्ट्रीय प्रौद्योयोगिकी दिवस 2018 मनाया गया

- भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योयोगिकी दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरूआत वर्ष 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी। यह दिवस भारत की विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योयोगिकी में विकास को दर्शाता है। इस अवसर पर तकनीकी संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- इस दिन प्रस्तुतिकरण, इंटरैक्टिव सत्र, प्रश्नोत्तरी, व्याख्यान और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। 11 और 13 मई, 1939 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर पांच परमाणु परीक्षण किये थे। इसके उपलक्ष्य में आधिकारिक तौर पर भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई को घोषित किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 03 मई, 2018 को नई दिल्ली में 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार, गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार, जसारी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (पुरुष) पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार प्रदान किये।

- सभी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिये जाने के कारण कई कलाकार पुरस्कर वितरण समारोह में शामिल नहीं हुये। इससे पहले 60 से अधिक विजेता कलाकारों ने जानकारी मिलने पर कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति कुछ ही पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे, यह घोषणा कर दी थी कि इस स्थिति में वे समारोह में शामिल नहीं होंगे।

  राष्ट्रपति ने केवल 11 विजेताओं को सम्मानित किया जैसे कि दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मरणोपरांत, श्रीदेवी को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, केजे यसुदास को बेस्ट मेल पेलेबैक सिंगर, रिद्धि सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और एआर रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता:

- अभिनेता विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को उनकी फिल्म 'मॉम' के लिए मिला।

  फिल्म नगर कीर्तन के लिए रिद्धि सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।

- बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार फिल्म न्यूटन को दिया गया है और 'न्यूटन' फिल्म के लिए एक्टर पंकज त्रिपाठी को विशेष पुरस्कार मिला है। इस साल की सर्वेश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर असमिया फिल्म विलेज रॉक स्टार को मिला है। वहीं बेस्ट पॉपुलर फिल्म के पुरस्कार के तौर पर बाहुबली 2(तेलगु) को चुना गया है।

विजेताओं की सूची

पुरस्कार	विजेता
1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म	विलेज रॉकस्टार (असमी)
2. इंदिरा गांधी अवार्ड	सिंजर
3. सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म	आलोरुक्कम
4. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म	म्होरक्या
5. सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म	बाहुबली-2
6. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	जयराज (बयानागम)
7. सर्वेश्रेष्ठ अभिनेता	अजीत कुमार (विवेगम)
8. सर्वेश्रेष्ठ सहायक कलाकार	फहाद फासिल

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

9. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री	दिव्या दत्ता (इरादा)
10. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार	नीता दास (बाल कलाकार)
11. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (पुरुष)	येसुदास
12. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक फिल्म	लद्दाख
13. सर्वश्रेष्ठ जसारी फिल्म	सिंजर
14. सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म	पद्दाई
15. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म	टू लेट्
16. सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म	दह
17. सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म	गाजी
18. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म	कच्चा लिंबू
19. सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म	तोंडीमुथुलम
20. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म	हेबेट्टू रामाक्का
21. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म	न्यूटन
21. सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म	मयूराक्षी
22. सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म	इशु
23. सर्वश्रेष्ठ एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स	बाहुबली-2
24. सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर	ए आर रहमान
25. पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म	इरादा
26. नर्गिस दत्त अवार्ड	धप्पा
27. दादा साहेब फाल्के अवार्ड	विनोद खन्ना
28. स्पेशल अवॉर्ड	पंकज त्रिपाठी (न्यूटन), पर्वती (टेक ऑफ)

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ज्यूरी

❑ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की दस सदस्यीय कमिटी के ज्यूरी के प्रमुख शेखर कपूर ने अवार्ड की घोषणा की इस ज्यूरी के अन्य सदस्य हैं स्क्रीनराइटर इम्तिआज हुसैन, गीतकार मेहबूब, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री गौतमी तडिमल्ला, अनिरूद्ध रॉय चौधरी, कन्नड़ के डायरेक्टर पी शेषाद्री, रंजीत दास, राजेश मपसुकर, रूमी जाफरी और त्रिपुरारी शर्मा विजेताओं को 3

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पुरस्कार मिलेंगे। ज्यूरी सदस्यों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर यह घोषणा की गई है।

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिये जाने वाले भारत को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जो वर्ष 1954 से दिये जा रहे हैं। यह पुरस्कार तीन खंडो में प्रदान किये जाते है; जिनमें फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन शामिल हैं। श्यामची आई (मराठी) पहली फिल्म थी जिसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा दो बीघा जमीन (हिंदी) तथा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य (बांग्ला) ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाली पहली फिल्में थीं।

दादा साहेब फाल्के अवार्ड

- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरसकार है। यह किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंम्भ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। यह पुरस्कार उस वर्ष के अंत में राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये और स्वर्ण कमल दिया जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिये जाने वाले भारत के काफी पुराने पुरस्कार हैं जो सन् 1954 से दिये जा रहे हैं। यह पुरस्कार तीन खंडों में प्रदान किये जाते है; फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन।

Call: 8899999931/34,7065202020, Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
A-1, Chandra House, Top Floor, Opp. ICICI Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-110009